



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 34]

शिमला, शनिवार, 30 अगस्त, 1986/8 भाद्रपद, 1908

[संख्या 35

विषय-सूची		
भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	814--822 तथा 840--842
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	822--827 तथा 843--845
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शल कमिशनर तथा कमिशनर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	827--832
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग	832--835
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और बिज्ञापन	835--836 तथा 846
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	836--840
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	---
---	अनुपूरक	---

30 अगस्त, 1986/8 भाद्रपद, 1908 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं:--

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या ई० एक्स० एन०-एफ० (17)-3/81, दिनांक 26 अगस्त, 1986	Directorate of State Lotteries उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग	Result of 14th Draw of "Shivalik Weekly" held at Shimla on 21-8-1986. हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 से संलग्न अनुसूची 'ए' की प्रविष्टि 1 में दर्शित केवल बसों और ट्रकों की चेसियों पर कर, व्योहारी के कराधेय आवर्त पर 10 प्रतिशत अधिशुल्क सहित साढ़े तीन पैसे प्रति रुपये की दर से तारीख 1-9-86 से उद्गृहीत होगा, इसके प्राधिकृत अंग्रेजी रूपान्तर सहित।

भाग-1- वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATION

Shimla-1, the 11th August, 1986

No. HHC/14-89/Jus/S/79-8818.—It is hereby notified that the Hon'ble Mr. Justice Hira Singh Thakur, Judge, has relinquished the charge of the office of the Judge, High Court of Himachal Pradesh, in the forenoon of August 10, 1986 on attaining the age of superannuation.

By order,
R. L. KHURANA,
Registrar.

सामान्य प्रशासन विभाग
ख-शाखा

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 16 अप्रैल, 1985

संख्या जी0ए0 बी0-2बी(3) 1/84.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री अमर सिंह ठाकुर, अवसर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश को 30-4-1985 दोपहर उपरांत उनके सेवाकाल पूर्ण होने पर सेवा निवृत्ति के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जुलाई, 1986

संख्या एक्स-एन-जी (1) 1/78-पार्ट.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः बहुदेशीय बैरियर स्वारघाट, जिला बिलासपुर के कार्यालय तथा स्टाफ के लिए रिहायशी मकान के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो, इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस समय इस उपक्रम से कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इस इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है :—

विवरणी

जिला: बिलासपुर

सब-तहसील: स्वारघाट

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा बि०
फतेहपुर	106	0 6
	107 तथा	0 10
	108	0 3
	109 तथा	0 8
	110	0 11
/		
किसा	5	1 18

आदेश द्वारा,
आर० के० आनन्द,
वित्तियुक्त तथा सचिव।

शिमला-2, 17 अक्टूबर, 1985

संख्या जी० ए० बी० 1-ए(4)-13/85.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 12 अगस्त, 1985 का प्रसंग जारी रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, सहर्ष यह आदेश देते हैं कि उप-मण्डल स्तरीय शिकायत तथा छाद्य एवं आपूर्ति सलाहकार समितियों की बैठकों की अध्यक्षता सम्बन्धित जिलों के जिलाधीश द्वारा की जायेगी।

ये आदेश तत्काल लागू होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव।

शिमला-2, 14 जनवरी, 1986

संख्या जी०ए०बी०-4-डी०(1)-29/84.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में डाक-तार विभाग द्वारा यू०एच० फ० स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिये भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या एफ-25(3)-जे०-ii, दिनांक 20-2-1957 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके नौवे कार्य करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को इस क्षेत्र की किसी भी भूमि में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर, कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (मब-डिवीजनल आफिसर, सिविल), चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरण		SPECIFICATION					
जिला : चम्बा		तहसील : चम्बा		District: CHAMBA		Tehsil: CHAMBA	
गांव/कस्बा	खसरा नं०	क्षेत्र बोधा विस्वा		Locality/Village	Khasra No.	Area Big.	Bis.
1	2	3	4	1	2	3	4
मुगला	1259189711	0	2	MUGLA	1259/897/1	0	2
	1040	0	7		1040	0	7
	16371129511	0	7		1637/1295/1	0	7
	96311	0	3		963/1	0	3
	964	0	5		964	0	5
	965	0	7		965	0	7
	1312197311	0	7		1318/973/1	0	7
	958	0	11		958	0	11
	959	0	8		959	0	8
	960	0	4		960	0	4
	1291/256	0	2		1291/956	0	2
	12931957	0	7		1293/957	0	7
	961	0	4		961	0	4
	962	0	4		962	0	4
	103911	0	3		1039/1	0	3
	16381129511	0	14		1638/1295/1	0	14
	13191973	0	5		1319/973	0	5
	97611	0	7		976/1	0	7
कित्ता ..	18	5	7		Kitta ..	18	5

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

By order,
Sd/-
Secretary.

(Authoritative English text of Himachal Pradesh Government Adhisuchna No. GAB-4 D (1) 29/84 dated 14-1-1986 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B—SECTION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th January, 1986

No. GAB-4D (1) 29/84.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Central Government, at public expence for the public purpose, namely for the construction of U.H.F station at Chamba, by the Posts and Telegraph Department, it is hereby notified that the land in the locality specified below is likely to be required for the above purpose.

2. This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 and in pursuance of powers delegated by the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. F. 25 (3) 57-II, dated the 20th February, 1957, to all whom it may concern.

3. In exercise of the powers conferred by the afore-said section, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

4. Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within thirty days of the publication of this notification file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition (Sub-divisional Officer—Civil), Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh.

शिमला-171002, 22 फरवरी, 1986

संख्या जी० ए० बी० 1-ए (4)-28/85.—इस विभाग के अधिसूचना संख्या जी० ए० डी० (डी) (ए)-4-1/80 (पाठ) दिनांक 6 अगस्त, 1982 का अधिक्रमण करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय शिकायत तथा खाद्य एवम् आपूर्ति सलाहकार समिति का पुनः गठन निम्न प्रकार से करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

1. मुख्य मन्त्री अध्यक्ष
2. प्रभारी मन्त्री, खाद्य एवम् आपूर्ति उपाध्यक्ष
3. श्रीमती विद्या स्टोक्स, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सदस्य विधान सभा

4. कांग्रेस (आई) पार्टी के प्रतिनिधि:

1. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य (आई) ।
2. श्री हरदयाल चौधरी, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य (आई) ।
3. श्री देव राज नेगी, प्रधान युवा कांग्रेस सदस्य
4. श्री सिधो राम, महासचिव युवा कांग्रेस सदस्य

5. संसद सदस्य:

1. श्री रोशन लाल, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
2. श्रीमती ऊषा मल्होत्रा, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
3. श्री आनन्द शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
4. श्री नारायण चन्द पराशर, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
5. श्रीमती, चन्द्रेश कुमारी, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

6. विधान सभा सदस्य:

1. श्री नेहरु सिंह विधायक सदस्य
2. श्री मिलखी राम गोमा, विधायक सदस्य
3. श्री हीरा सिंह पाल, विधायक सदस्य
4. श्री जगदेव चन्द, विधायक सदस्य

7. बोर्ड के अध्यक्ष :

1. श्रीमती सरला शर्मा, अध्यक्ष, खादी एवम् ग्रामोद्योग सदस्य बोर्ड ।
8. अत्येक जिला स्तरीय समिति में से एक गैर सरकारी सदस्य जिसे सरकार द्वारा अध्यक्ष, जिला स्तरीय समितियों द्वारा सिफारिश किये गये 3 व्यक्तियों की सूची में से चुना जाना है ।
9. श्री ज्ञान सिंह नेगी, भूतपूर्व विधायक, एडवोकेट, कल्पा, जिला किन्नौर । सदस्य
10. भाई सुन्दर सिंह, भूतपूर्व विधायक, नाहन, जिला सिरमौर सदस्य
11. श्री हेम चन्द सूद, प्रधान, हिमाचल प्रदेश व्यापार मण्डल, जिला सोलन । सदस्य
12. श्री सी0सी0डी0 जन, हिमाचल कंडक्टर्ज, सपरून, जिला सोलन । सदस्य
13. गुल्जार मुहम्मद भारती, संयोजक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक कक्ष, गांव व डा0 नागवाँई, जिला मण्डी । सदस्य
14. सूबेदार रामरक्खामल, ऊना, हिमाचल प्रदेश सदस्य
15. मेजर विधि चन्द, जिला हमीरपुर सदस्य
16. श्री बालक राम भूतपूर्व विधायक, कश्यप निवास, कैथू, शिमला-3 सदस्य

सरकारी सदस्य

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सदस्य
2. वित्तायुक्त (विकास) सदस्य
3. वित्तायुक्त (राजस्व) सदस्य
4. आयुक्त एवम् सचिव (सामान्य प्रशासन) सदस्य
5. आयुक्त एवम् सचिव (उद्योग) सदस्य
6. आयुक्त एवम् सचिव (स्वास्थ्य) सदस्य
7. आयुक्त एवम् सचिव (लोक निर्माण) सदस्य
8. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवम् सचिव सदस्य (बहुद्देशीय परियोजना एवम् विद्युत)
9. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री सदस्य
10. सचिव (स्वायत्त शासन विभाग) सदस्य
11. सचिव (खाद्य एवम् आपूर्ति) सदस्य-सचिव
12. पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश सदस्य
13. पंजीयक, सहकारी सभायें, हिमाचल प्रदेश सदस्य
14. निदेशक, खाद्य एवम् आपूर्ति सदस्य
15. प्रबन्ध निदेशक, मिविल मण्डलाइज कारपोरेशन सदस्य

इस समिति के गठन के आदेश तुरन्त लागू होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव ।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 फरवरी, 1986

संस्था होम-ए-(ए)(1)-5/80.—पंजाब पुलिस नियम, 1934 जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लागू है के नियम 1.10 के अध्यायन सहित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का दूसरा अधिनियम) की धारा (2) के खण्ड (एस) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूचि के स्तम्भ (2) में दिए गए मौजाजात/गांवों, जो कि स्तम्भ (3) में दिए गए पुलिस थाना के कार्यक्षेत्र में पड़ते हैं, को स्तम्भ (4) में

दी गई पुलिस चौकी के कार्यक्षेत्र में तत्काल तबदील करने के लिए सहर्ष आदेश देते हैं :—

अनुसूचि

क्र0सं0	नाम मौजाजात/गांव	पुलिस थाने का नाम जिसमें अब तक शामिल थे	पुलिस चौकी जिसमें इस अधिसूचना जारी होने पर शामिल हुए
1	2	3	4
1.	टिक्कर	थाना पालमपुर	पुलिस चौकी पंचरुखी ।
2.	अन्दरीता	"	"
3.	सलयाणा	"	"
4.	अगोजर	"	"
5.	मनोंयारा	"	"
6.	दयोग्रां	"	"
7.	पट्टी	"	"
8.	भोरा	"	"
9.	थन्डोल	"	"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 मार्च, 1985

संख्या 38-98/69-एग्र-सैक्ट.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री हंस राज अकरोट, भूतपूर्व विधायक का हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम, शिमला के निदेशक मण्डल तथा उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिनांक 7 फरवरी, 1985 बाद दोपहर से सहर्ष स्वीकार करते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (उद्यान) ।

सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः* भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन* के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता व्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, मण्डी को एतद्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू-अर्जन, व्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

*बन्ध सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु ।

संख्या सिचाई-(II)-1-5/85-मण्डी. शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

विस्तृत विवरणी

विस्तृत विवरणी		1	2	3	4	5
जिला: मण्डी		तहसील: सदर				
गांव	खसरा नं०	क्षेत्र				
		बी०	बि०	वि०		
1	2	3	4	5		
रौ/241	28/1	0	1	14	384/2	0 7 10
	29/1	0	2	8	368/1	0 0 14
	27/1	0	2	16	369/1	0 8 0
	35/1	0	0	3	623/1	0 6 8
	46/1	0	0	3	623/2	0 0 12
	45/1	0	1	10	623/3	0 2 16
	261/1	0	1	12	608/1	0 0 12
	1017/285/1	0	2	2		
किता ..	8	0	12	8	किता .. 47	6 19 11

संख्या (सिचाई) II-1-6/85-मण्डी.

शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

सकरोह/
2941235/1110/
700/1/1

1 0 3

संख्या सिचाई (II) 1-5/85-मण्डी-III.

शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

तमरोह	860/775/374/1	0	1	0
किता ..	1	0	1	0

*ग्राम रौ के पम्प हाउस के निर्माण हेतु।

संख्या (सिचाई) (II)-1-5/85-रौ-II 0

शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

रौ

1064/529/1	0	3	11
1066/531/1	0	2	16
519	0	1	8

संख्या सिचाई (II)-1-5/85-मण्डी.

शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

किता .. 3 0 7 15

तमरोह चीतड़ा/ 242.	645/1	0	0	4
	644/1	0	1	14
	640/1	0	1	5
	639/1	0	5	7
	638/1	0	1	6
	953/635/1	0	6	1
	634/1	0	8	1
	629/1	0	4	8
	629/2	0	15	6
	629/3	0	0	14
	624/1	0	4	15
	624/2	0	0	12
	624/3	0	3	13
	379/1	0	6	8
	383/1	0	3	14
	382/1	0	2	4
	381/1	0	0	3
	380/1	0	0	2
	433/1	0	4	16
	432/1	0	1	4
	596/1	0	2	11
	595/1	0	1	12
	594/1	0	0	7
	592/1	0	2	18
	648/1	0	2	0
	652/1	0	1	19
	649/1	0	1	4
	248/1	0	11	0
	247/1	0	1	13
	294/1	0	2	1
	305/1	0	0	6
	302/1	0	0	19
	302/3	0	2	8
	310/1	0	0	8
	311/1	0	3	4
	301/1	0	1	13
	300/1	0	3	3
	300/2	0	0	7
	367/1	0	0	9
	384/1	0	1	0

*बन्धु घाटी सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु।

संख्या (सिचाई) II-1-6/85-मण्डी.

शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

चतरोर/
293

287/1	0	11	19
302/2/1	1	10	5
302/1/1	0	12	19
859/305/1	1	2	7
848/506/1	1	4	5
204/1	0	12	12
203/1	0	11	12
205/1	0	0	18
308/1	0	16	2
316	0	18	0
328/1	1	16	2
329	0	9	5
310/1	0	2	8
318/1	0	16	10
317/1	1	15	6
330/1	0	5	17
322/1	2	8	6
860/305/1/1	2	6	0

किता .. 18 18 0 13

संख्या (सिचाई) (II)-1-6/85-मण्डी

शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

गोड़ा गगल/
214

622/1	0	15	16
629/1	0	6	8
630 सालम	0	4	8
631/1	0	2	15
631/2	0	0	13
626/1	1	3	8
642/1	0	5	11
633/1	0	17	12
634/1	0	7	8
626/1/1	0	6	2

1	2	3	4	5
	797/768/733/1	0	15	8
	501/1	0	14	2
	500/1	0	8	4
	492/1	0	3	14
	790/750/361/1	2	9	6
	498/1	0	16	14
	496/1	0	8	6
	499/1	1	1	1
	560/1	0	0	12
	495/1	0	6	4
	495/2	0	2	3
	620/1	1	8	9
	566/1	0	6	8
	621/1	0	1	16
	621/2	0	1	0
	627/1	0	0	12
	504/1	0	7	17
	504/2	0	4	18
	564/1	1	18	10
	590/1	0	19	7
	586/1	0	0	8
	589/1	0	14	12
	588/1	0	18	12
	766/733/1	0	9	15
	799/768/633/1	0	5	10
	798/768/733/1	0	18	14
	637/1/1	0	0	6
	502/1	1	3	18
	503/1	0	1	18
	507/1	0	13	4
कित्ता	40	22	11	7

आदेश द्वारा,
बी० बी० टण्डन,
सचिव।

INDUSTRIES DEPARTMENT

CERTIFICATES OF APPROVAL

Shimla-2, the 28th June, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-II.—This is to certify that M/s D. D. Ahuja, 555-A, Krishna Colony, Gurgaon is approved as a person who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto the 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that Shri Rajib Abbi, SC/6, w.e.a. Karol Bagh, New Delhi is approved as a person who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

The certificate already granted and which expired on the 31st December, 1985 is renewed upto 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that M/s Surinder Kumar Kamala Devi, V.&P.O. Kamroo, is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals

except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that M/s Ajay Ayri Atma Ram Sharma, Village Bangran, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta, District Sirmaur is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto 31st December, 1986.

Shimla-171002, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that M/s Smt. Vidya Vati Sharma, 5, Lehn Bhawan, Shimla-1 is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that M/s Banor Lime and Quarrying Gram Udyog Workers Samiti, Banor is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto the 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that Shri P. L. Jalam c/o M/s Rama Cement Ltd., Karol Bagh, New Delhi is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto the 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that M/s V.K. Sood, Engineers & Contractors Pvt. Ltd., Chandigarh is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto the 31st December, 1986.

By order,
O. P. YADAV,
Commissioner-cum-Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 28 फरवरी, 1985

संख्या 8-7/80-श्रम-II.—इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 26-2-1984 का अधिक्रमण करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या LXIII 1948) की धारा 8 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु श्री बी०डी० शर्मा को सारे हिमाचल प्रदेश के लिए निरीक्षक तुरन्त नियुक्त करने के आदेश सहर्ष देते हैं। श्री बी०डी० शर्मा का मुख्य कार्यालय शिमला होगा।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

[Authoritative English text of Himachal Pradesh Government Notification No. 8-7/80 Shram-II dated 22-2-1985 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]

Shimla-2, the 28th February, 1985

No. 8/7/80-Shram-II.—In supersession of this Department Notification of even number dated the 24th February, 1984 and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 8 of the Factories Act, 1948 (Act No. LXIII of 1948), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri B.D. Sharma as Inspector for whole of Himachal Pradesh with Headquarters at Shimla for the purposes of the said Act with immediate effect.

By order,
Sd/-
Special Secretary.

शिमला-2, 14 अक्तूबर, 1985

संख्या 8-12/81-श्रम.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम को सेवाओं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या-14) की प्रथम अनुसूचि के अन्तर्गत आता है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जनोपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

और यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं को जन उपयोगी सेवा छः महीने तक घोषित करना अनिवार्य है।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) व उपखण्ड (VI) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा खाद्य एवं आपूर्ति निगम की उक्त सेवाओं को जन-उपयोगी सेवा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छः माह तक की अवधि के लिए सहर्ष तुरन्त घोषित करते हैं।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 3 मार्च, 1986

संख्या 8-16/80-श्रम-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सर्वश्री जवाला सिंह फिटर और श्री तिलक राज टर्नर, भूतपूर्व कर्मचारी मैसर्स सलेचा केबल प्राइवेट लिमिटेड, मैहतपुर तथा प्रबन्धकगण मैसर्स सलेचा केबल प्राइवेट लिमिटेड, मैहतपुर, जिला कुना, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित हैं कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं०-14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-ए के अन्तर्गत निर्मित श्रम अधिकरण को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :-

“क्या श्री जवाला सिंह फिटर और तिलक राज टर्नर भूतपूर्व कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करना सही और न्यायसंगत है, यदि नहीं तो सर्वश्री जवाला सिंह फिटर और श्री तिलक राज टर्नर भूतपूर्व कर्मचारी किस सहायता और निश्चित क्षतिपूर्ति धन राशि के पात्र हैं।

शिमला-171002, 6 मार्च, 1986

संख्या 15-3/86-एल०ई०पी०.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि थिरानी कैमिकल्ज वर्क्स यूनिशन, निहालगढ़, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर तथा थिरानी कैमिकल्ज लिमिटेड, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के मध्य नीचे दिए गये विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित हैं कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है;

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :-

“क्या मजदूरों की निम्नलिखित मांगें :-

1. मजदूरों की राजपत्रित छुट्टियों के दिन कार्य देने पर पी०एल० दिया जाए
2. सभी मजदूरों को साल में 12 पी०एल० दिया जाए
3. सालाना बोनस 20 प्रतिशत दिया जाए
4. यूनिशन को 25 छुट्टी साल की दी जाए
5. चौकौदारों को ठण्डा भत्ता दिया जाए
6. प्रति कर्मचारी को 40 रु० साइकिल भत्ता दिया जाए
7. प्रत्येक शिफ्ट में शिफ्ट कर्मचारियों को 30 मिनट का लन्च दिया जाए।

सही और न्यायसंगत है यदि नहीं तो थिरानी कैमिकल्ज वर्क्स यूनिशन, निहालगढ़, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर किस सहायता और निश्चित क्षतिपूर्ति धन राशि का पात्र है।”

शिमला-171002, 6 मार्च, 1986

संख्या 15-3/86-एल०ई०पी०.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री राधा किशन प्रोसैस आपरेटर/श्री बावन प्रसाद प्रोसैस आपरेटर/श्री राम प्रसाद फिटर, श्री राम कान्ति यादव, प्रोसैस आपरेटर/श्री हसमुद्दीन अन्सारी प्रोसैस आपरेटर/श्री शर्मा नन्द वैल्डर और थिरानी कैमिकल्स वर्क्स यूनिशन, निहालगढ़ पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित हैं कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 12 की उपधारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-ए के अन्तर्गत निर्मित श्रम अधिकरण की नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :-

“क्या कामगारों की 2-12-85 की मांगें 19-1-85 के समझौता को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत और सही हैं और उन्हें क्या सहायता मिलनी चाहिए। मांगें निम्नलिखित हैं :-

- (i) क्या छः कामगारों को निकालना सही और न्यायसंगत है और किस सहायता के हकदार हैं।
- (ii) सभी मजदूरों को वर्दी टैरीफाट साल में एक या सूती साल में दो दी जाये और इसके साथ-साथ एक जूता एवं जुराब का जोड़ा भी दिया जाए।
- (iii) लेबर कलौनी में एक पानी की टांकी एवं शोचालय एवं स्नानगृह दी जाए।
- (iv) कालौनी में एक डिस्पेंसरी खोली जाए।

(v) सभी कामगारों के पे स्केल नीचे लिखे तरीके से दिये जाएं:-

- (क) उप-फिटर 1000 रुपये से 1200 रु० प्रति माह दिया जाए
- (ख) फिटर 1000 रुपये से 1200 रु० प्रति माह वेतन दिया जाए
- (ग) इलेक्ट्रिशियन 1000 रु० से 1200 रु० प्रति माह वेतन दिया जाए।
- (घ) व्यालमरटेन्डेंट 1000 रु० से 1200 रु० प्रति माह वेतन दिया जाए।
- (ङ) फोरमैन 900 से 1100 रु० प्रति माह वेतन दिया जाए।
- (च) हैल्पर 800 रु० से 1000 रु० प्रति माह वेतन दिया जाए।
- (छ) चौकीदार 800 रु० से 1000 रु० प्रति माह वेतन दिया जाए।
- (ज) सामान्य इन्क्रीमेंट 15 प्रतिशत दी जाए।
- (झ) यूनियन के आफिस के लिए एक कमरा दिया जाए तथा नोटिस के लिए नोटिस बोर्ड दिया जाए।

2. क्या कामगारों की हड़ताल कानूनी है, यदि हां तो किस सहायता के हकदार हैं।”

शिमला-171002, 2 जुलाई, 1986

संख्या 8-16/80-भाग-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्रीमती मोहीनी बाला सुपुत्री राजा राम, एम०एल०सी०, (डेली वेज), ग्राम तथा डाकखाना दसूहा, तहसील अम्ब, जिला ऊना और सहायक अभियन्ता, विद्युत सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ऊना, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित हैं कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है;

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं:-

“क्या श्रीमती मोहीनी बाला डेली वेज मीटर लैजर वजर्क के पद से निकालना सही और न्यायसंगत है यदि नहीं तो श्रीमती मोहीनी बाला किस सहायता और निश्चित क्षतिपूर्ति धन राशि की पात्र है।”

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/अ
सचिव।

विद्युत विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-171002, 6 फरवरी, 1986

संख्या विद्युत-छ (5) 3/85.—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6-7 के अन्तर्गत नीचे दर्शायी गई अधिसूचनायें दिनांक 3-1-1986 को जो जारी की गई थीं, को दिनांक 3-2-1986 पढ़ा जाये।

अधिसूचनायें

नस्ति संख्या	दिनांक
1	2
1. विद्युत-छ (5)-5/85	3-1-86
2. " -1/85	"
3. " -34/85	"
4. " -3/85	"
5. " -33/85	"
6. " -59/85	"
7. " -30/85	"
8. " -49/85	"
9. " -58/85	"
10. " -47/85	"
11. " -44/85	"
12. " -26/85	"
13. " -45/85	"
14. " -53/85	"
15. " -48/25	"
16. " -28/85	"
17. " -51/85	"
18. " -52/85	"
19. " -56/85	"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विद्युत)।

बहुदेशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अप्रैल, 1986

संख्या विद्युत-छ (5)-5/86.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विजली बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी०सी०) के अर्थात् अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः 66 के० वी० लाइन आन्ध्रा से नोगली तक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिसर में जैसा कि नीचे विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, को जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उन के कमचारियों और धर्मिकों को इलाके में किसी भी

भूमि में श्रवण करने तथा सर्वेक्षण करने और उस द्वारा द्वारा अपेक्षित प्रयोजन प्रयोजन सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा, हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, थिसल बैंक, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी:

जिला : शिमला

तहसील : रोहड़ू

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	2	3
संजी	884/1	0 03 03
	885/1	0 00 77
	919/1	0 00 99
	446/1	0 00 21
	764/1	0 00 21
	405/1	0 00 14
	444/1	0 00 20
कुटू	200/1	0 00 81
	460/1	0 01 69
थमटाडी	555/1	0 00 81
	536/1	0 01 69
बछुछ	126/1	0 00 19
जधोठी	157/1	0 00 30
	266/1	0 00 32
कटेडी	796/1	0 01 00
जोली	433/1	0 00 91
सुगरी	162/1	0 01 21
	46/1	0 01 44
भमनौली	789/1	0 02 59
	731/1	0 01 05
	678/1	0 01 48
करालथ	111/1/1	0 01 05
भारकली	375/1	0 01 44
	52/1	0 01 90
चड़गांव	1358/1065/611/1	0 01 48
	558/1	0 00 74
सुग्धाभोडा	250/1	0 00 74
मसली	694/1	0 00 37
	695/1	0 00 37
	907/1	0 01 48
	555/1	0 02 22
डिसरानी	2256/640/1	0 00 37
	415/1	0 00 37
कुल कित्ता	33	0 33 57

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

राजस्व विभाग (पौंग बांध सैल)

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जनवरी, 1986

संख्या 4-1/85-पौंग सैल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः व्यास प्रोजेक्ट के पौंग बांध रिजर्वेयर क्षेत्र के प्रयोगार्थ टीका बनूरी, हदबस्त 42, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में स्थित भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतः एतद्वारा यह

अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनका इसमें सम्बन्ध है, घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, व्यास प्रोजेक्ट, तलवाड़ा को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश प्राप्त करें ।

3. भूमि का नक्शा भू-अर्जन समाहर्ता, व्यास प्रोजेक्ट, तलवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

विवरणी					
जिला : कांगड़ा		तहसील: देहरा			
गांव	खमरा नं०	हदबस्त	क्षेत्र		
			एच०आर०एस०		
1	2	3	4	5	6
वनूरी	23	42	0	17	62
	25		0	03	60
	26		0	09	69
	27		0	02	42
	28		0	00	98
	29		0	03	23
	30		0	04	84
	31		0	01	00
	32		0	09	12
	33		0	04	61
	34		0	02	91
	35		0	03	85
	36		0	07	29
	37		0	07	78
	38		0	11	51
	39		0	12	56
	40		0	02	30
	41		0	09	87
	42		0	01	33
	43		0	03	38
	44		0	01	56
	45		0	01	33
	46		0	04	31
	47		0	01	29
	48		0	00	32
	49		0	01	21
	50		0	01	89
	51		0	01	39
	52		0	07	41
	53		0	02	68
	54		0	01	08
	55		0	00	25
	56		0	00	87
	57		0	00	45
	58		0	01	75
	59		0	02	39
	60		0	00	75
	61		0	02	68
	62		0	00	78
	63		0	01	13
64		0	01	63	
65		0	00	85	
66		0	01	30	
67		0	01	04	
68		0	00	72	
69		0	00	70	
70		0	00	67	

[illegible]

शिमला-2, 21 जनवरी, 1986

संख्या 4-25/83-पौंग कक्ष.—हिमाचल प्रदेश सरकार लोक व्यवहार पर लोक प्रयोजन के लिए इसमें नीचे विनिर्दिष्ट भूमि अपेक्षित नहीं है।

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपत्र, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम रनियाल, तहसील देहश, जिला कांगड़ा के टी.का रनियाल खाम, हदवस्त सं० 110/3 में व्याप्त बांध के जलाशय क्षेत्र के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाहियों को, जिनकी बाबत पंजाब सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं० 6969/बी०पी०ए०/3561/62, तारीख 1-4-63 को जारी की गई थी और पंजाब राज्यपत्र, तारीख 12-4-63 में प्रकाशित की गई थी और उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन पञ्चातन्त्री घोषणा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं० 4-1/69-रैव-II, तारीख 18-1-69 द्वारा जारी की गई थी और तारीख 15-11-69 के हिमाचल प्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशित की गई थी प्रत्याहृत करते हैं ।

त्रिनिर्देश

जिल्हा : कांगडा

तहसील : देहरा

ग्राम/टीका	खमरा नं०	हतवस्तु नं०	क्षेत्र		
			क०	म०	एकड़
1	2	3	4	5	6
रनियाल	985/210	110/3	0	16	1.13
	213/1/1		0	19	

ग्रादेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के प्रमुखों और जिना मेजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं हस्ताक्षर

निदेशालय, भू-एकत्रीकरण विभाग,
शुद्धि पत्र

शिमला-2, 26 फरवरी, 1986

संख्या गज०भू०ए०(प)-मण्डो 50/80.—इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना अधीन धारा 14(1) हमीरपुर 50/80-4643-90, दिनांक 30-4-1984 में क्रमांक संख्या 519-520-521-522 पर गांव कयाण रोपा, बध्याण, सनाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला

विनिर्देश

जिला : कांगड़ा

तहसील: देहरा

ग्राम/टीका	खसरा नं०	हदबस्त नं०	क्षेत्र		
			क०	म०	एकड़
1	2	3	4	5	6
घनोर बत्ता	41211	7313	2	0	0.99
प्रथम भावा	51211		5	6	
	301211		0	8	
	321211		1	0	
	341211		1	15	

जोड़ : 10 9

मण्डी दर्शाये जा चुके हैं जो कि अब दोबारा अधिसूचना अधीन धारा 14(1) घुमारवीं 50/80 3382-3442, दिनांक 10-5-85 हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में क्रमांक संख्या 116-117-118-119 पर दर्शाये गए थे उसे रद्द समझा जावे।

हस्ताक्षरित/-
निदेशक,
भ-एकत्रीकरण विभाग ।

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा

कार्यालय आदेश

चम्बा, 10 फरवरी, 1986

संख्या पी0एन0टी0सी0एच0-10(147)/73-32.—यतः श्री जगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बखतपुर, विकास खण्ड मैहला को इस कार्यालय आदेश संख्या पी0एन0टी0सी0एच0-10(147)/73-5107 दिनांक 13 दिसम्बर, 1985 के द्वारा धारा 54(1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 व नियम 77 हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के प्रावधानानुसार पंचायत निधि के दुरुपयोग के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया था और यह भी उपरोक्त श्री जगत राम, प्रधान से प्राप्त स्पष्टीकरण विचारोपरान्त असन्तोषजनक पाया गया।

अतः मैं, एस0 सी0 नेगी, उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो कि मुझे धारा 54(1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन प्राप्त हैं एतद्वारा श्री जगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बखतपुर को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि उक्त श्री जगत राम अपने पद का कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बखतपुर को तत्काल सम्भाल दें।

एस0 सी0 नेगी,
उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा।

कार्यालय जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, फरवरी, 1986

संख्या पी0सी0एच0-10जी0आर0-1217.—क्योंकि श्री रमेश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत धवाला, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा को वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व की 5 वर्ष की अवधि के दौरान (जब वह पंचायत के प्रधान पद पर कार्यरत थे) निम्नलिखित विभिन्न दुराचरण के कार्य करने का दोषी पाया गया था:—

1. उन्होंने मास 3/79 से 6/85 तक पंचायत निधि की राशियाँ अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी तथा इनका दुरुपयोग किया जब कि नियमानुसार वह कोई भी धनराशि अपने पास नहीं रख सकते थे। इससे ग्राम पंचायत को प्रधान द्वारा अनियमित रूप से रखी गई राशियों पर मिचने वाले व्याज से वंचित होना पड़ा।
2. दिनांक 30-6-79 तथा 30-6-80 को प्राप्त व्याज की राशि क्रमशः 18 रुपये 60 पैसे तथा 180 रुपये 26 पैसे को रोकड़ की आय की ओर दर्ज न करके व्यय की तरफ बकाया नकद से घटा कर राशि का दुरुपयोग किया।
3. दिनांक 27-2-80 से 24-9-80 तक सहकारी सभा से प्राप्त नकद राशि व्याज मुबलिंग 292 रुपये 73 पैसे का दुरुपयोग किया।
4. सहकारी सभा का बचत लेखा दिनांक 2-6-79 को अनियमित तौर पर खोलना तथा पंचायत के प्रस्ताव बिना सहकारी सभा व डाकघर के बचत लेखों से विभिन्न राशियाँ निकालना जो कि नियमों के विपरीत था।
5. पंचायत निधि से किए गए विभिन्न कार्यों पर मुबलिंग 5011 रुपये 40 पैसे के व्यय की पंचायत से स्वीकृति प्राप्त न करना।
6. मुबलिंग 12289 रुपये 91 पैसे की धनराशि सभा निधि से बिना स्वीकृति विभिन्न योजनाओं पर व्यय करना जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ था।
7. दिनांक 31-8-85 को सभा निधि मु0 335 रुपये 52 पैसे घटे में कर दी गई।

अतः मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1970) की धारा 57 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम, 70 के अधीन उक्त श्री रमेश चन्द, प्रधान को इस नोटिस द्वारा सूचित करता हूँ कि वह उपरोक्त बारे अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को 15 दिन के भीतर-भीतर प्रेषित करें कि उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही क्यों न व्यवहार में लाई जावे। इस अवधि के भीतर यदि उनका उत्तर प्राप्त न हुआ तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस बारे कुछ नहीं कहना तथा एक पक्षीय कार्यवाही प्रमल में लाई जायेगी।

हीरा लाल नाशाद,
अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा।

कार्यालय जिला, दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा

कार्यालय आदेश

कल्पा, 26 जुलाई, 1986

नं0 कनर-100/63-1-2009-13.—ग्राम पंचायत चारंग, विकास खण्ड पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या III, दिनांक 15 मई, 1986 द्वारा चारंग में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तव, जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं मैं ग्राम सभा क्षेत्राधिकार चारंग के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम चारंग में पशु फाटक स्थापित करता हूँ जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत चारंग धारा 18 (1) (एफ) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

विवेक श्रीवास्तव,
जिला दण्डाधिकारी, किन्नौर; कल्पा।

कार्यालय जिलाधीश, मण्डी, हिमाचल प्रदेश

आदेश

मण्डी, 15 जनवरी, 1986

संख्या पी0 सी0 एन0-233-8(1)/63-271-276.—क्योंकि श्री मिथु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी को पंचायत निधि के अपहरण/छतहरण के मामलों में संलिप्त होने के कारण उन्हें इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0 सी0 एन0-मण्डी 233-8(1)/63-1205-1211, दिनांक 26 मार्च, 1985 के अन्तर्गत प्रधान पद, ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी में निलम्बित किया गया था।

और क्योंकि वे ग्राम पंचायत धर्मपुर के मास सितम्बर, 1985 के चुनाव में पुनः प्रधान पद पर निर्वाचित हुए हैं तथा उन का प्रधान पद, ग्राम पंचायत धर्मपुर पर बने रहना उचित नहीं समझा जाता है।

अतः मैं, राजवन्त सन्धु, जिलाधीश मण्डी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत निहित हैं, श्री मिथु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर, तहसील सरलाघाट, जिला मण्डी को प्रधान पद, ग्राम पंचायत धर्मपुर, से निलम्बित करती हूँ तथा आदेश दिया जाता है कि यदि उन के पास पंचायत की कोई सम्पत्ति हो तो वे तुरन्त उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर को सौंप दें तथा पंचायत को किसी प्रकार की कार्यवाही में भाग न लें।

मण्डी, 15 जनवरी, 1986

संख्या पी0 सी0 एन0-मण्डी-14-10/83-264-270.—क्योंकि ब्रह्मा नन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भराडू, विकास खण्ड दंग, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी को अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी, के कार्यालय आदेश संख्या पी0 सी0 एन0-मण्डी-14-10/63-4561-66, दिनांक 31-8-85 के अन्तर्गत पंचायत निधि अपहरण/दुरुपयोग

के मामलों में प्रधान पद, ग्राम पंचायत भराड़, तहसील जोगिन्द्रनगर, से निलम्बित किया गया था।

और क्योंकि ब्रह्मानन्द मास सितम्बर, 1985 के पंचायत चुनाव में पुनः प्रधान पद, ग्राम पंचायत भराड़ पर निर्वाचित हो चुके हैं तथा उन का प्रधान पद, ग्राम पंचायत भराड़ पर बने रहना उचित नहीं समझा जाता है।

अतः मैं, राजवन्त सन्धु, जिलाधीश मण्डी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझ में पंचायत अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत निहित हैं श्री ब्रह्मानन्द को प्रधान पद, ग्राम पंचायत भराड़ से निलम्बित करती हूँ तथा आदेश दिया जाता है कि उन के पास पंचायत की यदि कोई चल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त उप-प्रधान, ग्राम पंचायत भराड़ को सौंप दिया जाये। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे निलम्बन काल में पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग न लें।

राजवन्त सन्धु,
जिलाधीश, मण्डी।

INDUSTRIES DEPARTMENT

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 2nd November, 1985

No. Ind./Loan/31/9975-78.—Whereas a notice was served on Smt. Chhering Dolma w/o Shri Chhering Nimee, V. & P. O. Bhuntar, on 1-1-83 under section 23/27 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Smt. Chhering Dolma to pay to me the sum of Rs. 1000/- (rupees one thousand only) plus interest on or before 31-1-83 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 1000/- (rupees one thousand only) plus interest is due from the said Smt. Chhering Dolma and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in her name including book debts, stocks, shares and premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee or sureties S/Shri Dorje s/o Shri Budh Ram, r/o V.&P.O. Bhuntar and Shri Gilu s/o Shri Bhiku, r/o Sharabai Kothi, Khokhan.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H.P.

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 7th November, 1985

No. Ind./Loan/742/10062-65.—Whereas a notice was served on Shri Nand Lal s/o Shri Panchi Ram, V. & P. O. Samshi on 25-8-1982 under section 23/27 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Nand Lal to pay to me the sum of Rs. 1108.35 (rupees one thousand one hundred eight and thirty-five paise only) plus interest on or before 19-9-82 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 1709.60 upto date is due from the said Shri Nand Lal and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in

his name including book debts, stocks, shares and premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee or sureties S/Shri Govind Singh s/o Shri Durga Singh, r/o Vill. & P. O. Shamshi and Shri Ram Nath s/o Shri Ram Chand, r/o Vill. & P. O. Manali.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H.P.

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 29th November, 1985

No. Ind./Loan/733-10501-04.—Whereas a notice was served on Shri Ramesh Kumar Prop. M/s Radiant Wood Works, Akhara Bazar, Kullu on 23-12-1982 under section 23/27 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Ramesh Kumar to pay to me the sum of Rs. 1700/- plus interest on or before 31-1-1983 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 2200/- plus Rs. 73.48/20 (upto date interest) is due from the said Shri Ramesh Kumar and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in his name including book debts, stocks, shares and premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H. P.

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 29th November, 1985

No. Ind./Loan/10513-16.—Whereas a notice was served on Shri Tashi Ram s/o Shri Ram Dyal, Vill. Ciyal, P.O. Manali, on 27-12-1982 under section 23/27 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Tashi Ram to pay to me the sum of Rs. 1000/- plus interest on or before 31-1-83 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 7000/- plus interest upto date is due from the said Shri Tashi Ram and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in his name including book debts, stocks, shares and premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H. P.

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 28th February, 1986

No. Ind./Loan/505-757-59.—Whereas a notice was served on Shri Tashi Ram s/o Shri Salo Ram, Village Jater, P. O. Katrain on 24-12-82 under section 23/27

of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Tashi Ram to pay to me the sum of Rs. 400/- plus interest on or before 31-1-83 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 400/- plus interest is due from the said Shri Tashi Ram and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in his name including book debts, stocks, shares, premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee or sureties S/Shri Durga Singh s/o Anant Ram, Vill. Chajogi, P. O. Naggar and Megh Singh s/o Roop Dass, Vill. Jater, P.O. Katrain.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H. P.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Government at public expense for a public purpose*. It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the said* purpose.

The declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh P. W. D. is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

3. A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, H. P. P.W.D., Shimla-3.

*Construction of Chawai-Khanag road.

No. SE-II-R-54-5/85-20051-55.

Shimla, the 20th November, 1985.

SPECIFICATION

District: KULLU

Tehsil: ANNI

Village 1	Khasra No. 2	Area Big. Bis. 3 4
KHANI	1317/1	0 12
	1316/1	0 2
	1144/1	0 12
	1143/1	0 1
	1075/1	0 6
	1078/1	1 1
	1074/1	0 2
	1074/2	0 2
	1071/1	0 7
	1072/1	0 3
	1063	0 6
	1061/1	0 1
	1064/1	0 8
	1027/1	0 2
	1030/1	0 6
	1028/1	0 3
	1029/1	0 4
	1021/1	0 3
	1023/1	0 1
	1022	0 8
	929/1	0 1
	813/1	0 2

1	2	3	4
	812/1	0	9
	814/1	0	3
	822/1	0	13
	824/1	0	1
	823/1	0	1
	827/1	0	13
	802/1	0	7
	699/1	0	10
	698/1	0	1
	701/1	0	5
	700/1	0	4
	703/1	0	1
	704/1	0	5
	2463/1	0	1
	2461/1	0	1
	2457/1	0	14
	2458/1	0	13
	1993/1	0	5
	2019/1	0	4
	2018/1	0	2
	2017	0	10
	1995/1	0	8
	1997/1	0	3
	1996/1	0	1
	1998/1	0	5
	1999/1	0	5
	1986/1	0	2
	1985/1	0	1
	1970/1	0	7
	1967/1	0	13
Total kitta ..	53	14	0

No. SE-II-R-54-5/85-20056-60.

Shimla-3, the 20th November, 1985.

KOILA	3560/1	0	15
	3546/1	0	1
	3558 Salam	0	4
	3552/1	0	2
	3559/1	0	1
	3553/1	0	1
	3556/1	0	4
	3555/1	0	2
	3590/1	0	1
	3785/1	0	1
	3731/1	0	4
	3732/1	0	8
	3730/1	0	1
	3733/1	0	2
	3737/1	0	1
	3737/2	0	3
	3743/1	0	1
	3741/1	0	8
	3742/1	0	5
	3709/1	0	14
	3708/1	0	2
	3694/1	0	3
	3695/1	0	9
	3696/1	0	17
	3697/1	0	13
	3736/1	0	13
Total kitta ..	26	6	16

District: SHIMLA

Tehsil: JUBBAL

*Construction of Anti-Shabar road.

No. SE-II-R-54-2/85-20349-53.

Shimla, the 22nd November, 1985.

BOHARAR	37/2/1	0	1
	46/1	1	5
	114/66/1	0	4
	34/1	0	3
	48/1	0	18
	65/1	0	5

1	2	3	4
	113/66/1	0	18
	20/1	0	12
	38/1	0	1
	37/1/1	1	11
	125/33/1-2	0	12
	123/17/1	0	3
	64/1	0	6
	102/12/1	0	11
	16/1	0	5
	79/3/1	1	6
	79/2/1	0	5
	15/1	0	15
Total kitta ..	19	9	11

No. SE-II-R-54-2/85-20339-43.

Shimla, the 22nd November, 1985.

JHATRI KANOT	441/78/1	0	1
	610/204/1	1	1
	637/499/205/1	0	17
	611/204/1	0	13
	205/1/1	0	6
	502/206/1	1	5

Total kittas .. 6 4 3

No. SE-II-R-54-2/85-29344-48.

Shimla-3, the 22nd November, 1985.

CHEANG DHARMANA	341/1	0	17
	725/616	0	1
	339/1	1	6
	340/1	0	5
	333/1	0	2
	600/1	0	2
	723/615/1	0	1
	329/1	0	2
	330/1	0	5
	361/1	1	4
	599/1	0	7
	601/1	0	1
	717/612	0	1
	727/617/1	0	1
	729/618/1	0	1
	715/611/1	0	2
	400/1	0	6
	713/610	0	1
	331/1	0	4
	360/1	0	17
	587/1	0	4
	731/603	0	2
	358/1	1	0
	602/1	0	1
	719/613/1	0	1
	721/614/1	0	1
	751/692/619/1	3	19
	328/1	0	6
	338/1	2	4
	702/699/640/1	5	4
	701/641/1	0	9
	701/641/2	16	1
	701/641/3	0	7
	300/1	1	11
Total kitta ..	34	37	16

S. K. AGGARWAL,
Superintending Engineer,
2nd Circle, H.P. P.W.D., Shimla-3.

Hamirpur, the 6th January, 1986

No. SE-VIII/W-3/LA-HMR/85-557-62.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Himachal Pradesh Government at the public expense for a public purpose, namely for the construction of approach road to Gasoti Khad bridge on Hamirpur-Jahu Road

in km 7, it is hereby notified that land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to acquisition of the said land in the locality may, within thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, H.P. P.W.D., Hamirpur.

SPECIFICATION

District: HAMIRPUR

Tehsil: HAMIRPUR

Mauza	Tikka	Khasra No.	Area K. M.	
1	2	3	4	5
UGIALTA	LAMB- LOO	1007/903/1	0	16
		902/750/1	0	04
		901/750/1	0	12
		900/750/1	0	15
		751/1	0	06
		752/1	0	11
		907/753/1	0	05
		779/1	1	02
		780	0	02
		782	0	01
		783/1	0	01
Total ..			4	15

P. C. BISHT,
Superintending Engineer,
8th Circle, H.P.P.W.D., Hamirpur

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH
DEPARTMENT

NOTIFICATION

Una, the 21st June, 1986

No. SE-IPHU/L.A./Paper/86-3035-38.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Himachal Pradesh Government at public expense for a public purpose namely for c/o Tubewell No. 39 at Kathari, it is hereby declared that the land in the locality described below is likely to be acquired for the said purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality may, within 30 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition, H.P. P.W.D., Hamirpur.

SPECIFICATION

District: UNA

Tehsil: AMB

2959/2425

0

5

Banjar Kadeem

Village

Khasra No.

Area
K. M.

Remarks

Total

0

13

1

2

3

4

KUTHIARI

2958/2425

0

8

Banjar Kadeem

S. P. SHARMA,
Superintending Engineer,
I & P H Circle, Una.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेंशियल कमिशनर, कमिशनर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

बहुदेशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएँ

शिमला-171 002, 25 अप्रैल, 1986

संख्या एम 0 पी 0 पी 0 (2)-56/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार आशुलिपिक के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय आशुलिपिक (वर्ग 3 पद) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1986 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय में आशुलिपिक के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम आशुलिपिक
2. पदों की संख्या 1 (एक)
3. वेतनमान 570-15-600/20-700/25-850-30-1080 रुपये
4. वर्गीकरण श्रेणी-3 (तीन)
5. चयन पद अथवा अचयन पद अचयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु 18 से 32 वर्ष तक

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी जो पहले से सरकार की सेवा में हैं: परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों तथा अन्य वर्गों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेजन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सम्बन्धी ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त

टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने/आयोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख से की जायेगी।

टिप्पणी-2.—अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित ग्रहण आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

आवश्यक:

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य ग्रहण।
- (1) मैट्रिक; और (2) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और अंग्रेजी टंकण कला में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और हिन्दी टंकण-कला में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड क्रमशः।

वांछनीय:

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में नियुक्ति विद्यमान भिन्न दशाओं को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

लागू नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक ग्रहण प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है जैसी सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

टिप्पणी.—जब कभी स्तम्भ-2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्धों को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किया जायेगा।

11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिसमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।

- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है:—
- (क) भारतीय नागरिक, या
 - (ख) नेपाल की प्रजा, या
 - (ग) भूटान की प्रजा, या
 - (घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या
 - (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देश कीनिया, यूगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंज़ानिया (भूतपूर्व टांगानिका और ज़ंजीबार), ज़ाम्बिया, मालवी, जेयार तथा इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो। ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जायेगा जब उसे भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद की नियुक्ति के लिए चयन।

सीधी भर्ती के मामले में इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग उचित या समीचीन समझे लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार अवधारित किया जायेगा।

16. आरक्षण

सेवा में नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति जहां सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन

है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

[Authorised English text of this Government notification No. MPP-B (2) 56/84, dated 25-4-1986 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Shimla-2, the 25th April, 1986

No. MPP-B (2)-56/84.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Stenographer in the Department of Electrical Inspectorate, Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' appended to this notification, namely:—

1. Short title & commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Recruitment & Promotion Rules for the post of Stenographer (Class III Services) in the Department of Electrical Inspectorate, 1986.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

ANNEXURE—A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF STENOGRAPHER IN THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICAL INSPECTORATE

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Name of the post | Stenographer |
| 2. Number of posts | 1 (One) |
| 3. Scale of Pay | Rs. 570-15-600/20-700-25-850-30-1080 |
| 4. Classification | Class-III |
| 5. Whether selection or non-selection post. | Non-selection. |
| 6. Age for direct recruits | Between 18 and 32 years: |

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government:

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled castes/tribes candidates and other categories of persons to the extent permissible under general or special orders of the Himachal Pradesh Government:

Provided that the employees of all the public sector Corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous

bodies and are/were finally absorbed in the services of such corporations/autonomous bodies after the initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

Note-1.—Age limit for direct recruits will be reckoned from the last date fixed, for receipt of applications/lists of eligible candidates from Employment Exchanges by the Commission

Note-2.—Age and experience for direct recruits relaxable at the discretion of the commission in the case of candidates otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

Essential:

(i) Matric, and

(ii) Should possess a speed of 100 words per minute of shorthand in English and 80 words per minute of shorthand in Hindi and with type-writing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi respectively.

Desirable:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.

Not applicable.

9. Period of probation, if any.

Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be reduced to writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled by various methods.

100% by direct recruitment

Note.—Provisions of rule 10&11 are to be revised by the Government in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, as and when the number of posts under rule 2 are increased.

11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer grades from which promotion, deputation/transfer to be made.

Not applicable

12. If a D.P.C. exists, what is its composition.

Not applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

As required under law.

14. Essential requirement for direct recruits.

A candidate for appointment to any service or post must be,—

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Nepal, or
(c) a subject of Bhutan, or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b) (c) (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India /Government of Himachal Pradesh.

15. Selection for appointment by direct recruitment:

Selection for appointment to these posts in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test, if Commission so consider necessary or expedient by a written test/a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes etc. issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be record in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person or post.

शिमला-2, 12 मई, 1986

में अन्तिम रूप से आर्मलित किए गए हैं।

संख्या एम0पी0 पी0बी0 (2) 58/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय विभाग में इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार, चालक के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय चालक (वर्ग-3 पद) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1986 है।
(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय में चालक (वर्ग-3 पद) के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. पद का नाम | चालक |
| 2. पदों की संख्या | 2(दो) |
| 3. वेतन मान | 400-10-450/15-525/15-600 रुपये। |
| 4. वर्गीकरण | वर्ग-3 (तीन) |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद | अचयन |
| 6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु। | 18 से 32 वर्ष तक : |

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी जो पहले ही सरकार की सेवा में हैं :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों तथा अन्य वर्गों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु संबंधी ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् उन निगमों/स्वायत्त निकायों

टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने या नियोजनालय से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची की प्राप्ति की नियत अन्तिम तारीख से की जाएगी।

टिप्पणी-2.—अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित अर्हता आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले आवश्यक :
व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक (1) आठवीं पास या इसके समकक्ष ;
(2) उसके पास चालन अनु-ज्ञप्ति होनी चाहिए।
(3) उसके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चालन प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
(4) पहाड़ी क्षेत्र में हल्के वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले लागू नहीं।
व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है जैसी कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रति नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

टिप्पणी.—जब कभी स्तम्भ-2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाती है, तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्धों को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किया जाएगा।

11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा। लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति जैसी कि सरकार द्वारा समय-विद्यमान हो तो उसकी समय पर गठित की जाए। संरचना।

13. भर्ती करने में किन परि- जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो। स्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्न-लिखित रूप में होना आवश्यक है :—

(क) भारतीय नागरिक ; या
(ख) नेपाल की प्रजा ; या
(ग) भूटान की प्रजा ; या
(घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हों ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका के देश कीनिया, यूगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सके किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जायेगा जब उसे भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद की नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग उचित या समीचीन समझे लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार अवधारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण.—सेवा के लिए नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसी लिए जो कारण हैं उन्हें अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

आदेशानुसार,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

[Authorised English text of this Government notification No. MPP-D (2) 58/84, dated 12-5-1986 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

M.P.P. & POWERS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th May, 1986

No MPP-B (2) 58/84.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver in the Department of Electrical Inspectorate, Himachal Pradesh, as per Annexure "A" appended to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Himachal Pradesh Recruitment and Promotion

Rules for the post of Driver (Class III Services) in the Department of Electrical Inspectorate, 1986.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRIVERS (CLASS-III) IN THE DEPARTMENT OF ELECTRICAL INSPECTORATE HIMACHAL PRADESH

1. Name of post	Driver
2. Number of posts	2
3. Classification	Class-III
4. Whether selection or non-selection post.	Non-Selection
5. Scale of pay	Rs. 400-10-450/15-525-600
6. Age for direct recruitment.	Between 18 and 32 years.

Provided that upper age-limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in the service of the Government:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Tribes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employee of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after the initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

Note 1.—Age limit for direct recruits will be reckoned from the last date fixed for receipt of applications/list of eligible candidates from Employment Exchanges by the Commission.

Note 2.—Age and experience for direct recruits relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates otherwise well-qualified.

7. Minimum educational qualifications required for direct recruits. Essential: (i) Middle pass or its equivalent; (ii) should possess a valid driving licence; (iii) should possess a certificate of driving from I.T.I. or from any other recognised institution; and

- (iv) Two years experience of driving light vehicles in hilly area.

Desirable :

Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions

Not applicable.

9. Period of probation, if any.

Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/deputation/transfer and the percentage of vacancies by each method.

100% by direct recruitment. Note 1.—Provisions of Rule 10 and 11 are to be revised by the State Government in consultation with the H.P. P.S.C., as and when the number of posts under rule 2 are increased or decreased.

11. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.

Not applicable.

12. If a D.P.C. exists, what is its composition.

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

As required under law.

14. Essential requirement for direct recruits.

A candidate for appointment to any service or post must be:—
(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Nepal, or
(c) a subject of Bhutan, or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st of January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
(e) a person of Indian origin

who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intension of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India/State Government.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination/interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India/Government of Himachal Pradesh.

15. Selection for appointment by direct recruitment.

Selection for appointment to these posts in case of direct recruitment shall be made on the basis of a *viva voce* test or if the commission so considers necessary or expedient, by a written test or by a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the commission.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes etc. issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax

Where the Government is of the opinion, that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person or post.

By order,
K. C. MAHAJAN,
Secretary.

भाग ४—स्थानीय स्वायत्त शासन : म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 दिसम्बर, 1984

संख्या पी 0 सी 0 एच 0 एच 0 ए 0 (5)-5/76.—क्योंकि श्री राम दाम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना,

हिमाचल प्रदेश पर श्री रणवीर सिंह, ग्राम सलोह को इष्टों का भट्ठा लगाने हेतु (No Objection Certificate) देने का आरोप है ;

और क्योंकि उक्त श्री राम दाम को इस आरोप हेतु निलम्बनाप्राप्त कारण बताओ नोटिस इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश, दिनांक 18-11-83 के अन्तर्गत दिया था और इस सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री राम दास को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (डी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सलोह के उप-प्रधान पद से निलम्बन का सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-171002, 24 मई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच-ए(5) 5/76—क्योंकि श्री राम दास उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना को श्री रणवीर सिंह, ग्राम सलोह को इष्टों का भट्ठा लगाने हेतु (No Objection Certificate) देन के आरोप में इस कार्यालय का आदेश संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-5/76, दिनांक 17-12-84 द्वारा निलम्बित किया गया था ;

और क्योंकि श्री राम दास ने उक्त निलम्बन के विरुद्ध अपील की थी जिस पर विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में श्री राम दास इस तरह का प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार नहीं रखता था परन्तु इस कोटाही के लिए निलम्बन एक बहुत बड़ा दण्ड समझा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54() में प्राप्त है, श्री राम दास उप-प्रधान के उपरोक्त निलम्बन आदेशों को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं तथा भविष्य में उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी भी देते हैं ताकि वह अपने सीमित अधिकारों तक ही अपने पद का प्रयोग करें।

हस्ताक्षरित/-,
अवर सचिव।

शिमला-171002, 24 मई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5) 230/76—क्योंकि श्री मन्द लाल प्रधान, ग्राम पंचायत मैहड़ी तथा अन्य 12 लोगों ने उप-प्रधान श्री बंशी राम के विरुद्ध अनियमितता तथा गबन के कुछ आरोप लगाये थे जिस पर अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, ऊना ने जांच की थी;

क्योंकि अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, ऊना ने अपनी जांच की रिपोर्ट में यह बात कही है कि किसी विशेष पदाधिकारी को सिद्ध आरोपों पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उस के लिए पंचायत के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं ;

और क्योंकि अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी पदाधिकारी विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन अधिकारों के अन्तर्गत जो उन्हें पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) में प्राप्त है वास्तविकता को जानने के लिए जिला पंचायत अधिकारी ऊना को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, ऊना के माध्यम से शीघ्र इस विभाग को भेजेंगे।

हस्ताक्षरित/-
निदेशक।

आदेश

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(4)-75/76-4—यतः गांव का क्षेत्र अर्थात् गांव डंगयार, गुम्मा, कामली तथा अम्बोटा (ग्राम सभा टकसाल) आंशिक रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार स्थानीय स्वशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना एच0एस0जी0ए0(4)-1/78, दिनांक 15-1-1979 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र परमाणु में सम्मिलित किया गया है;

और यतः कथित क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र परमाणु में सम्मिलित किए जान से उक्त ग्रामों का ग्राम सभा टकसाल अधिसूचित क्षेत्र परमाणु में विभाजन हो गया है ;

और यतः उक्त ग्राम के भाग जो कि अधिसूचित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में समाविष्ट नहीं हुए हैं अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम सभा में समाविष्ट करने हेतु अलग गांव घोषित किए जाने अपेक्षित हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 3(1) एफ0एफ0 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त गांव के अधिसूचित क्षेत्र को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उपरोक्त अधिनियम की धारा 4(1) के प्रयोजनार्थ सहर्ष पृथक गांव घोषित करते हैं:—

अनुसूची

2. अधिसूचित क्षेत्र परमाणु में आंशिक रूप में समाविष्टी से जो गांव प्रभावित हुआ का नाम—डंगयार

क्रमांक	कोष्ठ नं० 2 में वर्णित गांव के खमरा नम्बरान अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आये अर्थात् ग्राम सभा में मिलाये जाते हैं	कुल क्षेत्र	कोष्ठ 3 तथा 4 विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए इस घोषणा आदेश द्वारा रखा गया नाम
1	3	4	5
1.	4, 5, 38, 39, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 80।1 80।2, 80।1।1, 80।2।2, 80।2।1, 80।3।2, 80।3।1, 81।1, 86।1, 99, 107, 108 110, 117, 118।1, 148, 123, 126, 6 7, 18, 132।18, 22, 23, 24, 25, 26।1, 27, 28, 29, 30, 31।1, 31।2, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ता 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 128।75, 127।75, 76, 77।1, 77।2 86।2, 145/133, 134।1, 145।134, 135।2, 146। 103, 47।103, 106, 129। 112, 130।112, 114, 115, 149, 121, 181।121.	वीघा विस्त्रा 142 10	डंगयार (गांव क्षेत्र)
2.	1 ता 24 मिन तन, 29, 31, 35, 37 मिन, 38 मिन, 41।1, 43, 45, 47 मिन, 48, 50। 2, 52 मिन, 53, 54, 54।2, 55, 64 मिन, 148।65।1 148।65।2, 165।66, 166।66, 69, 150।70।1।1, 150।70/2, 150।70। 2।1, 150।70।2।2, 151। 70।1, 151।70।2, 71।1, 72।2, 74।1, 74, 78।1, 78।2, 79, 80।1, 80।2, 80।2।1, 80।2।2, 80।3, 80।4, 80।5, 80।7, 81, 82।1, 82।2।1, 83।1, 83।2।1, 86।2।2, 84।1, 86।1, 88।1, 89, 90। 1, 90।2, 91।1, 94।1, 95।1, 96।1, 96।2, 97।1, 99।1, 102।1, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117।45। 37, 12 मिन, 32 मिन, 65 मिन, 118 ता 140।3 तक बाकी रहे।	750 12	गुम्मा (ग्राम क्षेत्र)

1	2	3	4	1	2	3	4
		बीघा विस्वा					
	2. ग्राम: कामली	1043 16					एक और मुहाल "रिजर्व जंगल खालग" क्रम सं० 23 के रूप में जोड़ दिया जाये।
3.	711, 1771811, 911, 912, 1111, 20, 22, 188123, 174176, 175126, 27 ता 61 तक, 18162, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मिन ता 162 तक बाकी रहे।		कामली (ग्राम क्षेत्र)	4	31	त्रिपल	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे एक और मुहाल "रिजर्व जंगल धार पनयाली" क्रम संख्या 17 के रूप में जोड़ दिया जाये।
4.	2. ग्राम: अम्बोटा 1 ता 67 तक और 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ता 224, 235, 236, 237, 239, 243, 250, 265, 266, 279, 287, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 317, 320, 322, 325, 327, 330, 365, 367, 368, 369, 301, 386, 391, 398, 401, 402, 406, 410, 411, 412, 413, 425, 426, 430, 435, 436, 439, 440, 444, 449, 451, 456, 457, 458, 460, 461, 463, 465, 466, 467, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 ता 549 तक और 551 ता 964 तक बाकी रहा बाकी और 966 ता 1020 खसरा नं० तक।	2820 10	अम्बोटा (ग्राम क्षेत्र)	4	8	अम्ब पठियार	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे एक और मुहाल "काली धार" क्रम सं० 6 के रूप में जोड़ दिया जाये।
				4	41	सियालकड़	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे अंकित क्रम संख्या 8 के मुहाल "मनेरा बजड़ा" को मनेरा पड़ा जाये तथा एक और मुहाल "बजड़ा" क्रम संख्या 18 के रूप में जोड़ दिया जाये।
				4	43	चौकी ढोरियां (मझीया)	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे अंकित क्रम संख्या 18 के मुहाल "चौकी ढोरियां" रिजर्व धटेड़ को चौकी-ढोरियां पड़ा जाये तथा एक और मुहाल "रिजर्व धटेड़" के नाम से क्रम संख्या 21 के रूप में जोड़ दिया जाये।

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 7 मई, 1986

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (4) 16/76-12.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4(1) तथा 5(1) के अन्तर्गत प्राप्त है, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड पंचखुड़ी की ग्राम सभा गंगोटी का नाम बदल कर ठिकरी डूहकी रखने का सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-2, 7 मई, 1986

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (4) 16/76-12.—अधिसूचना संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (4) 16/76-7, दिनांक 28-10-83, जो जिला कांगड़ा की मुहालबन्दी के धारे में है, में निम्नलिखित शुद्धियां की जायें :—

विकास खण्ड का नाम : देहरा

विकास खण्ड की क्रम संख्या	ग्राम सभा की क्रम संख्या	ग्राम सभा का नाम	शुद्धि का विवरण
1	2	3	4
4	3	वरोगलाह	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे अंकित क्रम संख्या 7, 19 तथा 20 पर अंकित मुहाल कलाल लाहड़, पठियाल लाहड़ तथा गठियाल लाहड़ को हटाया जाये और मुहालों की संख्या को 1 से 17 कर दिया जाये।
4	26	डोलखरयाना	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे

शिमला-171002, 10 जुलाई, 1986

सं० पी० सी० एच०-एच० ए० (4)-56/76-7.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 (1) तथा 5 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं जिला शिमला की विकास खण्ड नारकण्डा की ग्राम पंचायत वारुवाग का नाम बदल कर ग्राम पंचायत थानेधार रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शिमला-171002, 10 जुलाई, 1986

सं० पी० सी० एच०-एच० ए० (4) 29/76-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा (1) तथा 5 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला हमीरपुर की विकास खण्ड भोरंज की ग्राम पंचायत खडूही का नाम बदल कर दिम्मी रखने का सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश

शिमला-171002, 17 जुलाई, 1986

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (3)-7/76.—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 6(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला सोलन की विकास खण्ड सोलन की तबगठित ग्राम सभा शमरोड के भाग 1 तथा 2 के रजिस्ट्रों को दिनांक 21-7-86 से 27-7-1986 तक पुनरावृत्ति करने तथा आपत्तियों की सुनवाई हेतु और निरीक्षण करने एवम् सत्यापन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश से,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 18 जुलाई, 1986

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)88/80.—क्योंकि श्री कृष्ण दत्त प्रधान, ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड मशोवरा, जिला शिमला के विरुद्ध जिला अंकेक्षण अधिकारी मुख्यावास द्वारा किए गये पुनः अंकेक्षण 2/86 के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां सामने आई हैं;

यह कि श्री कृष्ण दत्त (जो कि पिछले कार्यकाल 9/85 से पहले उप-प्रधान थे) वे 1984 में 2500/- रुपये सड़क निर्माण हेतु प्राप्त किये परन्तु इस राशि का खर्च पंचायत के लेखों में 1981 में आ चुका है जिन मजदूरों के हस्ताक्षर मस्ट्रोल पर हैं, वह दूसरे मस्ट्रोल पर उन मजदूरों के भी हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते;

यह कि मलवाणा जल योजना के लिये 1981 में वर्तमान प्रधान 550/- रुपये की राशि पाईप इत्यादि सामग्री के साथ दी परन्तु फिर भी 354.76 रुपये की पाईप एक फर्म से खरीदी दिखाई गई है और लेखा 2-9-1985 को प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए पंचायत का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं;

यह कि 300/- रुपये के मस्ट्रोल, जिसमें 6 दिन की मजदूरी सम्मिलित है में न तो दिनांक और न ही कार्य का विवरण अंकित है;

यह कि 11/85 तथा 12/85 के मस्ट्रोल में शिवदत्त को जहां मजदूर दिखाया है वहां 1/86 के मस्ट्रोल में उसे मिस्त्री दर्शाया गया है;

यह कि 11/85 तथा 12/85 के मस्ट्रोल में तथा इसी तरह 1/86 के मस्ट्रोल में क्रमशः 4 तथा 3 मजदूरों के हस्ताक्षर हैं जो कि एक ही व्यक्ति द्वारा किये लगते हैं;

यह कि 1/86 के मस्ट्रोल में सर्वश्री रामकृष्ण, अमर सिंह तथा भूप राम को एक-एक दिन की अधिक आदयगी की गई है क्योंकि इन आरोपों की वास्तविकता जानने के लिये जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री कृष्ण दत्त, प्रधान ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड मशोवरा के विरुद्ध लगे आरोपों की वास्तविकता

जानने के लिए परियोजना अधिकारी शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश शिमला के माध्यम से इस कार्यालय को एक माह के भीतर-भीतर प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव।

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 जुलाई, 1986

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (11)-22/85.—क्योंकि स्थानीय स्वशासन विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0-ए0 (4)-2/75, दिनांक 24 जनवरी, 1986 के अनुसार जिला ऊना में जो अधिसूचित क्षेत्र समिति गगरेट में ग्राम कलोह के 1168 किते की 2533 कनाल 10 मरले भूमि सम्मिलित करने का प्रस्ताव है;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र समिति गगरेट के गठन के फलस्वरूप ग्राम कलोह के शेष क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 3(1) (एफएफ) के अन्तर्गत शेष बचे भाग को ग्राम घोषित करना जरूरी होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 3 (1) (एफ एफ) के अन्तर्गत अनुच्छेद 2 में अंकित ग्राम कलोह के शेष भाग को कलोह नाम से ग्राम घोषित करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, अनुच्छेद 3 में घोषित ग्राम कलोह के लिये कलोह ग्राम सभा क्षेत्र स्थापित करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

भाग 5—व्यक्तिगत अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri D. P. Sood, District Judge, Kangra Division Camp at Chamba

बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

.. सायल।

H.M.A. No. 42/86

वनाम

Kamli Versus Madan Lal

Versus:

Shri Madan Lal son of Phinnu, resident of Kakena, Pargana Sherpur, Tehsil Bhattiyat, District Chamba.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above noted respondent is evading the service of the summons and cannot be served in the normal course of service. Hence this proclamation is hereby issued against him to appear in this court on the date fixed for hearing on 22-9-1986 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings will be taken against him.

Given under my hand and the seal of the court this the 29th day of July, 1986.

D. P. SOOD,
District Judge,
Kangra at Chamba.

Seal.

बमदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं०.... ता० दा० 1-7-86 ता० फैसला....

मोहन सिंह सुपुत्र कालू राम, वासी जिदवी, तप्पा पाहलू, तहसील

(1) भगत राम सुपुत्र ब्यालू राम, (2) जागीर सिंह, (3) सतदेव सुपुत्र पोहलो राम, (4) श्रीमती कमला देवी पत्नी ओंकार चन्द, (5) सुन्दर, (6) मोहन पिसरान गुलावा, (7) सर्व दयाल सुपुत्र रुणका, (8) हरी चन्द, (9) कृष्ण कुमार, (10) प्रकाश, (11) कश्मीरा, (12) हमीर सिंह, (13) अमर चन्द, (14) प्रेम चन्द, (15) जान चन्द, (16) कर्म चन्द, (17) रोंकी, (18) कांशी राम, (19) दलीपू, (20) रोशन, (21) कश्मीरा, (22) दया राम, (23) रिखी राम, (24) प्रीतम सिंह, (25) श्रीमती चानो देवी, (26) कर्मी देवी, (27) कमला देवी, (28) परमा नन्द, (29) दिफो, (30) विधि चन्द, (31) केवल राम, (32) जुल्फी राम, (33) चरण दास, (34) चुन्नु राम, (35) निक्का राम, (36) रत्न चन्द, (37) वोहरा, (38) कांशी, (39) निक्कू, (40) निक्का, (41) दुर्गी देवी बाल्दा नरैण, (42) गायत्री देवी, (43) विजय कुमार, (44) सन्तोष कुमारी, (45) सुमना देवी, (46) प्रोमिला देवी, (47) गरीबू सुपुत्र तोता, (48) अनन्त राम सुपुत्र लच्छमण, (49) चन्दू सुपुत्र नानकू, (50) हिमाचल प्रदेश सरकार बजरिया कुलैक्टर महोदय जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश.. मसूल अलैहम।

दरखवास्त बराए किये जाने तक सीम अराजी मुन्दरजा खाता नं० 17 खतौनी नम्बरान 20 ता 47, खसरा नम्बरान 5, 6, 4, 208।31 मिन, 208।31 मिन, 210।32, 280।8, 281।8, 279।8, 29, 285।21, 282।212, 287।216, 289।41, 290।41, 302।9, 304।206, 14, 17, 46, 284।21, 283।212, 314।37, 286।216, 288।41, 306।204, 305।206, 218।49, 294।20, 298।24, 301।9, 307।204, 303।206, 292।3, 296।22, 300।26, 203।11, 205।13, 198, 7 मिन, 270।12 मिन, 16, 19, 27, 7 मिन, 270।12 मिन, 15, 272।30, 43, 159, 278।40, 45,

10, 25, 28, 18, 23, 274133, 276138, 44, 58, 277140, 269112, 271130, 273133, 275138, कित्ता 66 रकबा तादादी 114 कनाल 13 मरले रकबा मजरूआ दाखन बाच्छ, गैर मजरूआ खारिज बाछ मुन्दरजा जमाबन्दी 1981 82 वाक्या टीका ठमाणी मंझली, मौजा लौहडर, त0 वडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकदमा में फरीक दोयम (मसूलअलैहम) को समन जारी किए गए परन्तु वह निश्चित तारीख पेशी पर हाजर अदालत न आ रहे हैं और तामील भी हस्ब जाबता नहीं हो रही है। अतः अब अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त फरीकदोयम को साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अतः बजरिया इश्तहार

राजपत्र उपरोक्त समस्त फरीक दोयम को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20-9-1986 को सुबह 10 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजर हो कर मुकदमा की पैरवी करें अन्यथा एक तरफा कार्य-वाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-7-86 को जारी हुआ।

मोहर।

एस0 एस0 चौधरी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वडसर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

भाग 6-भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th March, 1986

No. LLR-Leg-E(9)/86.—The following Ordinances recently promulgated by the President which have already been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I, are hereby republished in the Himachal Pradesh Government Rajpatra, for general information of the public:—

Sr. No.	Title	Date of the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section I in which the Acts were published
1.	The Administratibe Tribunals (Amendment) Ordinance, 1986 (1 of 1986).	22nd January, 1986.
2.	The Ravi and Beas Waters Tribunal Ordinance, 1986 (2 of 1986).	24th January, 1986.
3.	The Contract (Regulation and Abolition) Amendment Ordinance, 1986 (3 of 1986).	28th January, 1986.
4.	The Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 1986 (4 of 1986).	28th January, 1986.

Sd/-
Secretary (Law).

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 22nd January, 1986/Magha 2, 1907 (Saka)

THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986

(No. 1 of 1986)

Promulgated by the President in the Thirty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Administrative Tribunals Act, 1985.

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Ordinance may be called the Administrative Tribunals (Amendment) Ordinance, 1986.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of the long title.**—In the Administrative

Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title, after the words “any corporation”, the words “or society” shall be inserted.

3. **Amendment of section 2.**—In section 2 of the principal Act, clause (b) shall be omitted.

4. **Amendment of section 3.**—In section 3 of the principal Act,—

(a) clause (a) shall be re-lettered as clause (aa), and before clause (aa) as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

“(a) “Administrative Member” means a Member of a Tribunal who is not a Judicial Member within the meaning of clause (i);”;

(b) for clause (i), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(i) “Judicial Member” means a Member of a Tribunal appointed as such under this Act, and includes the Chairman or a Vice-Chairman who possesses any of the qualifications specified in sub-section (3) of section 6;

(ia) “Member” means a Member (whether Judicial or Administrative) of a Tribunal, and includes the Chairman and a Vice-Chairman;”;

(c) clause (n) shall be omitted;

(d) in clause (q), after the words “any corporation”, the words “or society” shall be inserted;

(e) after clause (r), the following clause shall be inserted, namely:—

“(rr) “society” means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or under any corresponding law for the time being in force in a State;”.

5. **Amendment of section 4.**—In section 4 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, or sub-section (1) of section 5, the Central Government may,—

(a) with the concurrence of any State Government, designate, by notification, all or any of the Members of the Bench or Benches of the State Administrative Tribunal established for that State under sub-section (2) as Members of the Bench or Benches of the Central Administrative Tribunal in respect of that State and the same shall exercise the jurisdiction, powers and authority of the Central Administrative Tribunal by or under this Act;

(b) on receipt of a request in this behalf from any State Government, designate, by notification, all or any of the Members of the Bench or Benches of the Central Administrative Tribunal functioning in that State as the Members of the Bench or Benches of the State Administrative Tribunal for that State and the same shall exercise the jurisdiction, powers and authority of the State Administrative Tribunal as if established by or under this Act for that State,

and upon such designation, the Bench or Benches of the State Administrative Tribunal or, as the case may be, the Bench or Benches of the Central Administrative Tribunal shall be deemed, in all respects, to be the Central Administrative Tribunal, or the State Administrative Tribunal for that State established under the provisions of Article 323A of the Constitution and this Act.

(6) Every notification under sub-section (5) shall also provide for the apportionment between the State concerned and the Central Government of the expenditure in connection with the Members common to the Central Administrative Tribunal and State Administrative Tribunal and such other incidental and consequential provisions not inconsistent with this Act as may be deemed necessary or expedient."

6. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), for the words "and other Members", the words "and Judicial and Administrative Members" shall be substituted;
- (b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
“(2) Subject to the other provisions of this Act, a Bench shall consist of one Judicial Member and one Administrative Member.”;
- (c) sub-section (3) shall be omitted;
- (d) in sub-section (4),—
 - (i) in the opening portion, the words, brackets and figure "or sub-section (3)" shall be omitted;
 - (ii) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
“(a) may, in addition to discharging the functions of the Judicial Member or the Administrative Member of the Bench to which he is appointed, discharge the functions of the Judicial Member or, as the case may be, the Administrative Member, of any other Bench.”;
 - (iii) in clause (c), for the words "the Vice-Chairman or, as the case may be, other Member of another Bench", the words "the Judicial Member or the Administrative Member, as the case may be, of another Bench" shall be substituted;
 - (iv) in clause (d),—
 - (1) for the words "three Members", the words "two Members" shall be substituted;
 - (2) the following proviso shall be inserted at the end, namely:—
“Provided that every Bench constituted in pursuance of this clause shall include at least one Judicial Member and one Administrative Member.”;
- (e) sub-section (5) shall be omitted;
- (f) in sub-section (6),—
 - (i) in the opening paragraph, for the words "an additional Bench", the words "a Bench" shall be substituted;
 - (ii) in the proviso, for the words "three Members", the words "two Members" shall be substituted;
- (g) in sub-section (7), the words "principal Bench and other" shall be omitted.

7. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (2),—
 - (i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
“(bb) has, for at least five years, held the post of an Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or”;

(ii) in clause (c), for the words "a Member", the words "a Judicial Member or an Administrative Member" shall be substituted;

(b) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member unless he—

(a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or

(b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that Service for at least three years.

(3A) A person shall not be qualified for appointment as an Administrative Member unless he—

(a) has, for at least two years, held the post of an Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or

(b) has, for at least three years, held the post of a Joint Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India,

and shall, in either case, have adequate administrative experience.”;

(c) in sub-sections (4) and (5), for the words "The Chairman", the words, brackets and figure "Subject to the provisions of sub-section (7), the Chairman" shall be substituted;

(d) in sub-section (6), after the words, brackets and figures "under sub-section (3) of section 4", the words so, brackets and figure "and subject to the provisions of sub-section (7)" shall be inserted;

(e) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(7) No appointment of a person possessing the qualifications specified in sub-section (3) as the Chairman, a Vice-Chairman or a Judicial Member shall be made except after consultation with the Chief Justice of India.”.

8. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act, in the *Explanation*, after the words "any corporation", the words "or society" shall be inserted.

9. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act,—

(a) in the opening paragraph, the words "principal Bench and each of the additional" shall be omitted;

(b) in the proviso, for the words "the Vice-Chairman, subject to the condition that the Vice-Chairman", the words "the Vice-Chairman or any officer of the Tribunal, subject to the condition that the Vice-Chairman or such officer" shall be substituted.

10. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1A) The officers and other employees of a Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.”.

11. Amendment of sections 14 and 15.—In sections 14 and 15 of the principal Act,—

(a) the words and figures "under article 136 of the Constitution", wherever they occur, shall be omitted;

- (b) after the word "corporation", wherever it occurs, the words "or society" shall be inserted;
- (c) after the word "corporations", wherever it occurs, the words "or societies" shall be inserted.

12. Amendment of section 18.—In sub-section (1) of section 18 of the principal Act,—

- (a) for the words "any additional Bench or Benches of a Tribunal is or are constituted", the words "any Benches of a Tribunal are constituted" shall be substituted;
- (b) the words "principal Bench and the additional Bench or additional" shall be omitted.

13. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act,—

- (a) in the *Explanation* below sub-section (1), after the word "corporation", at both the places where it occurs, the words "or society" shall be inserted;
- (b) in sub-section (2), for the words "as may be prescribed by the Central Government", the words "in respect of the filing of such application and by such other fees for the service or execution of processes, as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;
- (c) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Tribunal shall, if satisfied after such inquiry as it may deem necessary, that the application is a fit case for adjudication or trial by it, admit such application; but where the Tribunal is not so satisfied, it may summarily reject the application after recording its reasons."

14. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (2), for the words "after hearing of oral arguments, if any, allowed by the Tribunal in the circumstances of the case", the words "after hearing such oral arguments as may be adduced" shall be substituted;
- (b) in sub-section (3), for the words "holding any inquiry", the words "discharging its functions under this Act" shall be substituted.

15. Amendment of section 23.—In sub-section (2) of section 23 of the principal Act,—

- (a) after the word "corporation", the words "or society" shall be inserted;
- (b) for the portion beginning with the words "may appoint" and ending with the words "before a Tribunal", the words "may authorise one or more legal practitioners or any of its officers to act as presenting officers and every person so authorised by it may present its case with respect to any application before a Tribunal" shall be substituted.

16. Substitution of new sections for sections 25 and 26.—For sections 25 and 26 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

"25. Power of Chairman to transfer cases from one Bench to another.—On the application of any of the parties and after notice to the parties, and after hearing such of them as he may desire to be heard, or on his own motion without such notice, the Chairman may transfer any case pending before one Bench, for disposal, to any other Bench.

26. Decision to be by majority.—If the Members of a Bench differ in opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority, if there is a majority, but if the

Members are equally divided, they shall state the point or points on which they differ, and make a reference to the Chairman who shall either hear the point or points himself or refer the case for hearing on such point or points by one or more of the other Members of the Tribunal and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of the Members of the Tribunal who have heard the case, including those who first heard it."

17. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act, for the words, brackets and figures "no court (except the Supreme Court under article 136 of the Constitution) shall have", the following shall be substituted, namely:—

"no court except,—

- (a) the Supreme Court; or
- (b) any Industrial Tribunal, Labour Court or other authority constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) or any other corresponding law for the time being in force,

shall have".

18. Amendment of section 29.—In section 29 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), in the proviso, the words "or the Supreme Court" shall be omitted;
- (b) in sub-section (2),—
 - (i) after the word "corporation", wherever it occurs, the words "or society" shall be inserted;
 - (ii) in the proviso, the words "or the Supreme Court" shall be omitted.

19. Amendment of section 35.—In sub-section (2) of section 35 of the principal Act,—

- (a) in clause (a), for the words "three Members", the words "two Members" shall be substituted;
- (b) in clause (d), for the words "and the fees payable in respect of such application", the words "and the fees payable in respect of the filing of such application or for the service or execution of processes" shall be substituted.

20. Amendment of section 36.—In section 36 of the principal Act, in clause (a), the words "principal Bench and the additional" shall be omitted.

21. Provisions as to existing Members of Central Administrative Tribunal.—Every person holding office as Chairman, Vice-Chairman or other Member of the Central Administrative Tribunal immediately before the commencement of this Ordinance shall,—

- (a) if he possesses any of the qualifications specified for appointment as a Judicial Member under the principal Act, as amended by this Ordinance, be deemed, on and from such commencement, to have been appointed as a Judicial Member of such Tribunal; and
- (b) in any other case, be deemed, on and from such commencement, to have been appointed as an Administrative Member of such Tribunal.

ZAIL SINGH,
President.

S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 24th January, 1986/Magha 4, 1907 (Saka)

THE RAVI AND BEAS WATERS TRIBUNAL
ORDINANCE, 1986

(No. 2 of 1986)

Promulgated by the President in the Thirty-sixth Year
of the Republic of India.

An Ordinance to provide for the constitution of a Tribunal for the verification of the quantum of usage of water claimed by the farmers of Punjab, Haryana and Rajasthan from the Ravi-Beas system as on the 1st day of July, 1985, and the waters used for consumptive purposes and for the adjudication of the claim of Punjab and Haryana regarding the shares in their remaining waters;

Whereas paragraph 9.1 of the Punjab Settlement provides that the farmers of the States of Punjab, Haryana and Rajasthan will continue to get water not less than what they were using from the Ravi-Beas system as on the 1st day of July, 1985, and that waters used for consumptive purposes will also remain unaffected and the quantum of usage so claimed shall be verified by a Tribunal referred to in paragraph 9.2 of the said Settlement;

And whereas paragraph 9.2 of the said Punjab Settlement also provides that the claim of the States of Punjab and Haryana regarding the shares in their remaining waters will be referred for adjudication to a Tribunal to be presided over by a Supreme Court Judge;

And whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Ordinance may be called the Ravi and Beas Waters Tribunal Ordinance, 1986.

(2) It extends to the States of Punjab, Haryana and Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "Punjab Settlement" means the Memorandum of Settlement on the Punjab problem signed at New Delhi on the 24th day of July, 1985;

(b) "Tribunal" means the Ravi and Beas Waters Tribunal constituted under section 3.

3. **Constitution of Tribunal.**—(1) As soon as may be after the commencement of this Ordinance, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Tribunal to be known as the Ravi and Beas Waters Tribunal for the verification and adjudication of the matters referred to in paragraph 9 of the Punjab Settlement.

(2) The Tribunal shall be a single member Tribunal presided over by a person nominated by the Chief Justice of India from amongst persons who at the time of such nomination are Judges of the Supreme Court.

(3) The Tribunal may appoint two or more persons as assessors to advise it in any proceeding before it.

(4) The presiding officer of the Tribunal and the assessors appointed under sub-section (3) shall receive such remuneration, allowances or fees as may be specified by the Central Government.

4. **Adjudication of matters.**—(1) When a Tribunal has been constituted under section 3, the Central Government shall refer the matters specified in paragraph 9 of the Punjab Settlement to the Tribunal for verification and adjudication.

(2) The Tribunal shall investigate the matters referred to it and forward to the Central Government a report, within such period as may be specified in the reference under sub-section (1), setting out the facts as found by it and giving its decision on the matters referred to it.

(3) The Central Government shall publish the decision of the Tribunal in the Official Gazette, and such decision shall be final and binding on the parties to the proceeding before it and shall be given effect to by them.

5. **Filling up of vacancies.**—If, for any reason, a vacancy (other than a temporary absence) occurs in the office of the presiding officer of the Tribunal, such vacancy shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 3 and the investigation of the matters referred to the Tribunal may be continued by the Tribunal after the vacancy is filled from the stage at which the vacancy occurred.

6. **Powers of the Tribunal.**—(1) The Tribunal shall have the same powers as are vested in civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents and material objects;

(c) issuing commissions for the examination of witnesses or for local investigation.

(2) The Tribunal may require any State Government to carry out, or permit to be carried out, surveys and investigation as may be considered necessary for the verification or adjudication of any matter referred to it.

(3) Subject to the provisions of this Ordinance, the Tribunal may, by order, regulate its own practice and procedure.

7. **Bar of jurisdiction of Courts.**—Notwithstanding anything contained in any other law, no court shall have, or exercise, jurisdiction in respect of the matters which may be referred to the Tribunal under this Ordinance.

8. **Dissolution of the Tribunal.**—The Central Government shall dissolve the Tribunal after it has forwarded its decision to the Central Government.

9. **Ordinance to have over-riding effect.**—The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

ZAIL SINGH,
President.

S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 28th January, 1986/Magha 8, 1907 (Saka)

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) AMENDMENT ORDINANCE, 1986

No. 3 OF 1986

Promulgated by the President in the Thirty-seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970;

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Amendment Ordinance, 1986.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Act 37 of 1970.—In section 2 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(a) “appropriate Government” means,—

(i) in relation to an establishment in respect of which the appropriate Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), is the Central Government, the Central Government;

(ii) in relation to any other establishment, the Government of the State in which that other establishment is situate;’.

ZAIL SINGH,
President.S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 28th January, 1986/Magha 8, 1907 (Saka)

THE MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986

No. 4 OF 1986

Promulgated by the President in the Thirty-seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Motor Vehicles Act, 1939.

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 1986.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 47.—In section 47 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) (hereinafter referred to as the principal Act), in Explanation I below sub-section (1C), for the words and figures “sections 55, 63 and 68”, the words and figures “sections 55 and 68” shall be substituted.

3. Amendment of Section 63.—In section 63 of the principal Act,—

(a) in sub-section (11),—

(i) in the opening paragraph,—

(A) the words “in respect of such number of motor vehicles as the Central Government may specify in this behalf in relation to that State” shall be omitted;

(B) for the word and figures “sections 54, 55”, the word and figures “sections 45, 54” shall be substituted;

(ii) the proviso shall be omitted;

(b) sub-sections (11A), (11B) and (11C) shall be omitted.

4. Amendment of Section 68.—In section 68 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (ci),—

(i) for the words “, public carriers’ permits or national permits”, the words “or public carriers’ permits” shall be substituted;

(ii) the words and figures “or section 63” shall be omitted;

(b) in clauses (cii) and (civ), for the words “, public carriers’ permits or national permits”, the words “or public carriers’ permits” shall be substituted.

ZAIL SINGH,
President.S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.भाग 7-भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएँ
शून्यअनुपूरक
शून्य

PART I

उद्योग विभाग
अधिसूचना

शिमला-2, 23 अगस्त, 1986

महोदय उद्योग-6(छ:) 5-1/85.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास

निगम सीमित जो कि भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खण्ड (सी0सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव सराज माजरा-नुजरा, जुड़ी-खुद तथा जुड़ी-कला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया

जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करना अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अन्तर्गत, भूमि-अधिग्रहण समाहर्ता (उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि अर्जन करने के लिए आदेश प्राप्त करें ।

3. इस भूमि का नक्शा एवं अन्य कागजात भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किए जा सकते हैं ।

परिक्षेत्र

जिला : सोलन

तहसील: नालागढ़

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र	
		बीघा बिस्वा	
1	2	3	4
(1) सराज-माजरा-गुजरां	288	4	19
	305	5	10
	306	2	8
	307	1	13
	328	1	6
	298	1	5
	300	2	13
	301	0	13
	302	0	8
	303	1	14
	324	0	18
	325	0	17
	326	0	14
	329	1	7
	330	3	17
	327	6	4
	295	3	6
	287	3	16
	289	2	9
	290	0	15
	291	3	16
	293	0	11
	294	0	12
	296	1	3
	297	19	19
	304	5	1
	322	6	1
	312	1	15
	313	1	5
	315	0	17
	317	2	11
	321	5	8
	308	1	6
	309	1	0
	310	1	2
	311	1	4
	314	1	13
	347/285	1	0
	348/286	0	11
	316	0	18
	319	7	16
	320	0	9
	318	2	18
	346/285	2	11
	349/286	0	9
योग	45	118	2

(2) जुड़ी-खुद

52 मिन	5	0
54 मिन	1	10
55	2	11
56	6	7
133 मिन	2	2
57	5	16
116	1	9
117	1	3
118	2	8
132	0	14
134	1	9
52 मिन	10	10
54 मिन	4	16
128	0	7
131	0	16
133 मिन	0	13
20	1	19
32	0	15
33	0	16
21	1	18
31	1	8
19	0	13
34	1	9
36	2	1
37	1	9
38	0	6
39	2	16
35	5	3
121	2	6
123	0	9
124	1	18
115	8	4
40	1	7
42	2	2
46	2	9
47	2	15
49	21	17
53	4	16
17	1	19
18	2	8
263/45	1	8
265/45	3	5
274/65	0	10
271/65	2	19
276/66	2	1
277/68	1	2
3	1	0
4	1	3
51	1	19
264/45	1	9
266/45	3	5
270/65	0	19
272/65	1	8
273/65	1	2
275/66	2	0
278/68	1	3
122	2	12
125	0	18
129	0	9
130	0	13
135	6	5
136	0	3
9	3	14
44 मिन	1	12
10	0	18
16	3	10
119	2	5

1	2	3	4	1	2	3	4
	44 मिन	1	10		133	0	15
	120	2	7		23	1	4
	44 मिन	3	0		24	0	17
	12	0	18		29	13	16
	14	3	7		31	3	1
	15	1	0		37	4	8
	1	2	11		41	2	13
	2	0	16		121	1	19
	5	1	9		30	4	4
	6	1	16		120	0	7
	7	0	12		165	2	2
	28	7	7		166	0	18
	27	5	3		167	16	15
	22	3	3		169	4	13
	25	0	10		170	4	0
	29	1	11		39	2	8
	126	2	0		42	6	12
	58	1	6		43	2	14
	30	3	4		44	3	10
	13	0	11		45	0	17
	43	1	3		46	2	5
	50	0	14		49	2	3
	8	1	1		111	2	16
	41	0	10		112	13	15
	127	0	1		122	6	19
					123	3	15
योग ..	92	217	16		125	1	1
					128	1	0
					129	1	12
					126	0	5
					127	0	5
					130	0	5
					134	5	0
					138	0	10
					28	3	7
					27	2	15
					158	0	7
					160	2	4
					1	5	17
					2	0	16
					12	7	18
					13	4	11
					124	14	7
					17	5	0
					18	3	7
					53	3	12
					337/54	26	8
					338/54	10	18
					20	9	17
					9	1	4
					56	1	3
					350/57	0	17
					58	1	5
					351/57	2	8
					59	7	17
					352/142	1	12
					354/161	0	13
					162	0	14
					36	2	5
				योग ..	97	370	15
				कुल योग ..	3 गांव 234 खसरा	706	13

आदेश द्वारा,
श्री 0पी 0यादव,
आयुक्त एवं सचिव ।

PART II PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be acquired to be taken by the Government at the public expenses for a public purpose*. It is hereby declared that the land in the locality described below is likely to be acquired for the said* purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality may, within 30 days of the publication of the notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, H.P. P.W.D., Kangra.

*Construction of Tang-Uthragran-Ramehr-Baldhar-Jasaur road km. 2/0 to 10/0 (Portion km 2/0 to 8/0).

No. SEV-WS/LA/DH-4150-54.

Palampur, the 16th August, 1986.

SPECIFICATION

District: KANGRA

Tehsil: KANGRA

Mohal	Khasra No.	Area in Hect.
1	2	3
UPREHR/RAMEHR	119/1	0 00 16
	120/1	0 00 16
	126/1	0 00 75
	127/1	0 00 73
	128/1	0 01 75
	129/1	0 01 40
	130/1	0 00 92
	133/1	0 01 56
	134/1	0 04 10
	135/2	0 00 74
	141/1	0 00 20
	142/1	0 00 63
	143/1	0 01 26
	144	0 00 80
	145/1	0 01 97
	146/1	0 00 74
	147/1	0 00 06
	148/1	0 01 08
	148/2	0 00 09
	828/151/1	0 00 30
	154/1	0 00 06
	156/1	0 04 48
	157/2	0 03 76
	217/1	0 01 04
	227/2	0 00 24
	236/1	0 00 45
	236/2	0 00 16
	237/1	0 00 02
	268/1	0 00 34
	269/1	0 00 04
	270/1	0 01 44
	265/1	0 00 02
	266/1	0 00 45
	271	0 00 56
	272/1	0 02 24
	270/1	0 00 29
	273/1	0 00 12
	274/1	0 00 24
	278/1	0 00 04
	279/1	0 00 06
	280/1	0 02 72
	281/1	0 02 06

282	0 05 16
283/1	0 01 59
293/1	0 01 93
294/1	0 00 21
295/1	0 00 27
324/2	0 03 30
325/1	0 00 50
332/1	0 00 04
334/1	0 00 56
334/2	0 00 10
457/1	0 00 04
461/1	0 00 32
462/1	0 03 32
460/1	0 00 40
463/1	0 00 12
464	0 01 06
454/1	0 01 76
465/1	0 02 21
467/1	0 00 78
468/1	0 03 61
469	0 01 70
470/1	0 01 02
471	0 00 48
472/2	0 00 46
479/1	0 00 44
541/1	0 00 25
542	0 01 94
543/1	0 00 24
549/1	0 00 04
581/1	0 00 06
582/1	0 00 33
583	0 02 62
584/1	0 00 22
587/1	0 00 08
602/1	0 00 12
605/1	0 00 74
646/1	0 01 36
648/1	0 00 12
649	0 07 37
650/1	0 02 30
706/1	0 00 22
713/1	0 00 12
714/1	0 00 24
715/1	0 00 56
842/606/3	0 08 49
719/1	0 02 27
720/1	0 00 21
721/1	0 01 44
722/1	0 00 04
810/728/1	0 00 50

Total Kitta .. 93 1 03 61

BHUNEHR/RAMEHR	80/1/1	0 00 26
	83/1	0 00 46
	84/1	0 00 14
	86/1	0 00 13
	96/1	0 06 06
	616/97/2/1	0 00 28
	99/1	0 00 77
	100	0 04 96
	101/2	0 00 48
	102/1	0 01 87
	103/1	0 00 64
	104/1	0 00 24
	106/1	0 00 23
	107/1	0 00 15
	108/1	0 00 86
	124/1/1	0 01 58
	125/1	0 00 91
	127/1	0 00 20
	128/1	0 00 03
	151/1	0 00 36
	160/1	0 00 20
	209/1	0 00 08
	212/1	0 00 57
	213	0 03 96
	217/1	0 00 11
	218/1	0 00 18
	219/1	0 00 14
	227/1	0 00 08
	228/1	0 00 28

1	2	3	1	2
	232/1	0 00 32		562/2
	233/1	0 00 02		563/2
	234/1	0 00 15		563/4
	240/1	0 01 08		582/2/1
	241/1	0 02 03		582/3/1
	245/1	0 01 58		585/1
	246/1	0 01 28		
	249/1	0 02 28	Kitta ..	32
	250/1	0 00 05		
	255/1	0 00 04	ROD/SIHUND	157/2
	257/1	0 01 01		200/1
	258/1	0 00 06		208/2
	259/1	0 00 58		231/1
	277/1	0 00 60		232/2
	277/2	0 00 39		234/2
	278/1	0 02 09		235/1
	279/1	0 02 12		
	280/1	0 00 16	Kitta ..	7
	308/1	0 00 18		
	310/1	0 00 28	UPREHR/BALDHAR	382/1
	310/1	0 01 14		383/1
	311/1	0 00 04		387/1
	313/1	0 00 47		384/1
	314/1	0 00 16		388
	319	0 15 00		389/1
	320/1	0 01 50		390/1
	321/1	0 03 90		391/1
	322/1	0 02 94		386/1
	323/1	0 00 10		397/1
	341/1	0 00 12		398/1
	342/1	0 00 02		404/1
	344/1	0 00 08		408/1
	355/1	0 00 18		407/1
	356/1	0 00 52		409/1
	358/1	0 00 22		413
	504/1	0 01 76		421/1
	545/1	0 01 38		418/1
	546/1	0 00 30		419/1
	558/1	0 00 09		420
	559/1	0 01 90		422/1
	568/1	0 00 21		458/1
	568/2	0 01 28		459/1
	568/3	0 00 04		463/1
	569/1	0 00 06		381/1
	570/1	0 00 24		331/1
	590/1	0 03 80		332/1
	591/1	0 00 39		333/1
	592/1	0 00 14		338/1
	593/1	0 00 08		336/1
	594/1	0 00 13		335/1
	595/1	0 00 12		343/1
	596/1	0 00 30		344/1
				346/1
	Kitta ..	82	0 81 24	353/1
SIHUND	494/1	0 00 48		352/1
	496/2	0 04 97		354/1
	497/1	0 00 25		351/4
	499/2	0 01 92		350/1
	500/2	0 02 64		380/1
	514/2	0 02 25		377/1
	516/1	0 02 58		
	520/2	0 01 71	Kitta ..	41
	522/1	0 04 96		
	523/2	0 00 94	UPREHR/BALDHAR	372/2
	524/1	0 00 98		374/2
	536/2	0 02 10		380/3
	537/2	0 09 68		504/2
	538/1	0 00 24		505/1
	538/3	0 00 20		506/2
	545/1	0 05 99		507/1
	545/3	0 06 91		517/2
	546/1	0 00 36		521/2
	548/2	0 00 75		
	648/4	0 00 38	Kitta ..	9
	556/2	0 01 92		
	557/2	0 01 61	MANCHBAR/ BALDHAR	175/2
	558/1	0 01 38		175/3
	559/1	0 00 02		258/1
	560/1	0 00 24		261/2
	561/1	0 00 35		266/2

1	2	3
	268/1	0 00 89
	269/2	0 04 33
	270/2	0 00 30
	276/1	0 02 62
	324/280/1	0 03 41
	325/280/1	0 00 46
	281/1	0 00 38
	286	0 01 38
	288/1	0 02 72
	299/1	0 04 78
	300/1	0 01 83
Kitta ..	16	0 33 25
Grand Total ..	280	3 88 65

*Construction of Nagrota-Baldhar-Dhaloon road km.
5/80 to 8/250.

No. SEV-WS/LA-DH-4183-87.

Palampur, the 16th August, 1986.

DHALOON/ KARAPURA	1252/4/1	0 00 36
	1252/4/3	0 08 80
	1254/7	0 11 27
	305/1	0 07 28
	306/1	0 00 15
	1278/308/1	0 00 09
	1280/308/1	0 14 40
	1280/308/2	0 05 56
	1280/308/3	0 00 63
	309	0 37 81
	366/1	0 00 16
	367/1	0 00 48
	367/2	0 00 28
	465/1	0 00 31
	466/1	0 00 18
	468/1	0 00 98
	477/1	0 01 19
	478/1	0 00 27
	479/1	0 00 24
	488/1	0 00 12
	489/1	0 00 00
	490/1	0 00 06
	1266/597/1	0 22 39
	673/1	0 00 45
	675/1	0 00 24
	706	0 26 85
	707/2	0 05 76
	708/1	0 02 22
	710/1	0 00 46
	711/2	0 01 74
	712/2	0 03 82
	735/2	0 01 50
	736/1	0 00 20
	737/1	0 00 24
	737/2	0 00 14
	738/1	0 00 71
	739/1	0 01 14
	740/1	0 01 37
	741/1	0 00 78
	755/1	0 00 12
	771/1	0 01 51
	773/1	0 01 12
	774	0 05 60
	775	0 11 76
	776/1	0 00 70
	777/1	0 00 08
	779/1	0 00 56
	780/1	0 00 78
	781/1	0 00 90
	782/1	0 00 62
	853/1	0 00 06
	860/1	0 03 15
	880/1	0 00 36
	923/1	0 03 73
	926/1	0 00 21
	944/1	0 00 08

1	2	3
	957	0 00 08
	958/1	0 07 27
	959/1	0 01 50
	960/1	0 00 70
	970/1	0 00 64
	979/1	0 00 64
	980/1	0 02 08
	981/1	0 00 14
	983/1	0 00 40
	984/3	0 02 04
	985	0 04 55
	985/1	0 00 14
	987/1	0 00 15
	988/1	0 00 54
	989	0 00 34
	990	0 00 32
	1048/1	0 00 14
	1049/1	0 00 06
	1050/1	0 00 10
	1050/2	0 00 06
	1057/1	0 00 10
	1058/1	0 00 41
	1059/1	0 00 28
	1061/1	0 00 80
	1062/1	0 00 45
	1287/1064/1	0 00 38
	1068/1	0 00 04
	1069/1	0 00 42
	1072/1	0 03 35
	1074/1	0 00 57
	1075	0 13 33
	1076/1	0 00 44
	1077/1	0 00 60
	1078/1	0 00 15
	1079/1	0 00 14
	1080/1	0 00 29
	1081/1	0 01 04
	1084/1	0 02 24
	1097/1	0 00 98
	1098/1	0 00 10
	1099/1	0 00 20
	1100/1	0 00 04
	1107/1	0 00 36
	1108/1	0 00 91
	1109/1	0 00 06
	1143/1	0 00 12
	1145/1	0 00 10
	1146/1	0 00 14
	1149/1	0 00 14
	1151/1	0 00 58
	1245/1	0 00 06
Kitta ..	107	2 44 72
PATYALKAR	7	0 04 59
	304/1	0 00 20
	305/1	0 01 14
	306/1	0 00 06
	307/2	0 02 82
	309/1	0 00 66
	827/1	0 00 40
	821	0 00 16
	822/1	0 00 08
Kitta ..	9	0 10 11
DHALOON	1172/1	0 00 08
	1173/1	0 00 22
	1174/1	0 00 42
	1175/1	0 00 33
	1176	0 03 06
	1177/1	0 00 26
	1179/1	0 01 02
	1180/1	0 00 12
Kitta ..	8	0 05 51
G. Total	124	2 60 34

R. C. KALIA,
Superintending Engineer,
5th Circle, H.P. P.W.D., Palampur.

PART V

व अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शिमला, तहसील
व जिला शिमला

इशतहार जेर धारा 21, रूल 5, जाब्ता दिवानी

श्री चरण सिंह ठाकुर सुपुत्र स्वर्गीय हेतराम, सा 0 ग्राम बरमू, तह 0 व
जिला शिमला।

बनाम

श्रीमती सावित्री सुपुत्री रिजा मल, निवासी ग्राम केलटी बरमू, तह 0
व जिला शिमला।

दरखास्त बराए तबदीली खसरा गिरदावरी खेवट खतौनी नं 0 3,
8, खसरा नं 0 3, 4 किते 2 तादादी 0-12 बिस्वे मौजा जंगल महदूदा
शरावग, परगना पगोगी, तह 0 व जिला शिमला।

मुकदमा उपरोक्त में प्रतिवादी श्रीमती सावित्री को अदालत द्वारा
कई बार नोटिस जारी किए गए परन्तु बिना तामील वापिस आते रहे
अब हाल की तामील से पाया गया कि श्रीमती सावित्री 18-20 साल
से लापता है अब इशतहार द्वारा श्रीमती सावित्री देवी अगर कहीं
स्वयं पड़े तो वह मुकदमा हजा की पैरवी के लिए 5-9-86 को प्रातः
10 बजे अदालतन व वकालतन जवाब देही हाजिर अदालत आवे।
बसूरत गैर हाजरी कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22-8-86 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी
किया गया।

हस्ताक्षरित/-

मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शिमला।

व अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, देहरा

श्रीमती लूरो देवी विधवा हीरू पुत्र प्रसोतम दास, महाल खवली,
मौजा पाईसा, तहसील देहरा।

बनाम

(1) श्रीमती कौरा देवी, (2) जगदीशवरी देवी, (3) निर्मला
देवी, (4) कुमारी उषा देवी पुत्रियां सोमा देवी पुत्री ठाकर दास,
साकन खवली, तहसील देहरा व सर्व जनता।

तस्दीक इन्तकाल नं 0 22 मुहाल खवली, मौजा पाईसा, तहसील
देहरा, बरूए वसीयत जवानी दिनांक 19-4-81 मिन जानब श्रीमती
लूरो देवी बहक मुभाष चन्द।

प्रन्यायगण व सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता
है कि उन्हें कई बार नोटिस जारी किए गए कि वे बरवक्त तस्दीक
इन्तकाल हाजर आ कर अपना उजर एतराज पेश करें परन्तु वे
हाजर न आ रहे हैं। अतः उन्हें दोबारा बजरिया इशतहार सूचित
किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त इन्तकाल के मन्जूर होने
में कोई उजर या एतराज हो तो वे अदालतन या वकालतन हमारी
अदालत में बमकाम देहरा मिति 8-9-86 हाजर आकर कर सकते
हैं गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कारवाई अमल में लाई जा
कर फैसला इन्तकाल कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 7 माह अगस्त, 1986 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर
अदालत के जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-

मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील देहरा।

व अदालत जनाब शशिभूषण रिवाल, सहायक संग्रहकर्ता द्वितीय
श्रेणी (तहसीलदार), तहसील घुमारवीं, जिला विलासपुर, हिमाचल प्रदेश
परसराम, जीव राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव सिंहल,
परगना ल्यून, तहसील घुमारवीं।

बनाम

(1) रूपा विधवा धुंगर, निवासी ग्राम सिंहल, प्र 0 ल्यून, (2)
दुर्गा पत्नी यारू, निवासी ग्राम सिंहल, प्र 0 ल्यून, (3) राम प्रकाश
सुपुत्र गोविन्द, निवासी ग्राम वलोह, प्र 0 मुन्हाणी, (4) दुर्गा, (5) वंसी,
(6) मुख राम, (7) जगदीश, (8) सीतू पुत्रान बुहलू, निवासी
दकड़ी, (9) शाली सुपुत्र बेली, निवासी ग्राम दकड़ी, प्र 0 ल्यून।

मिसल नं 0 26/13

तारीख रजुआ 1-6-86

दरखास्त दरस्ती गिरदावरी अधीन धारा 37-38 वाक्या मौजा
सिंहल अराजी तादादी 1-7 विधा नं 0 ख 0 84 नं 0 खाता/खतौनी
52/74 मिन वाक्या मौजा सिंहल, प्र 0 ल्यून, तहसील घुमारवीं।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

हरगाह उपरोक्त मुकदमा दरस्ती गिरदावरी प्रतिवादीगण राम
प्रकाश व एल 0 आरज दुर्गा, वंशी, मुखराम, वाक्या मौजा दकड़ी,
को कई बार समन भेजने पर भी तामील अदालतन न हो सकी।
अतः अदालत को यकीन हो चुका है कि फीकदोयम की तामील अदालतन
न हो सकती है। अतः उपरोक्त फरीकदोयम को बजरिया इशतहार
अखबारी आर्डर 5 रूल 20 जाब्ता दिवानी सूचित किया जाता है कि
अगर उपरोक्त मुकदमा में फरीकदोयम को कोई उजर इतराज हो तो
दिनांक 3-9-86 को या इससे पूर्व बरवक्त 10 बजे सुबह अदालतन
व वकालतन अदालत आवें। बसूरत गैर हाजरी में एक तरफा कारवाई
अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 2-8-86 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर निशान कार्यालय
से जारी किया गया।

मोहर। शशिभूषण रिवाल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, घुमारवीं,
तहसील घुमारवीं।

HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION
NEW HIMRUS BUILDING, CIRCULAR ROAD
SHIMLA-171001

NOTICE

Shimla-171001, the 11th August, 1986

No. HPFC/4-3/67-V.—In pursuance of regulation 24
read with regulation 37 of the General Regulations of
the Corporation, it is hereby notified that a Special
General Meeting of the Share-holders of the Himachal
Pradesh Financial Corporation will be held at the Head
Office of the Corporation, New Himrus Building, Circular
Road, Shimla on MONDAY the 29th September, 1986
at 11.00 A.M. to transact the following business:—

To elect one director representing Co-operative
Banks in terms of Section 10A of the State
Financial Corporations Act, 1951 by the
Co-operative Banks who are shareholders of
the Corporation in place of Shri Manjit Singh
Dogra, who ceased to be a director of the
Corporation under the Act ibid.

2. It is further notified that the Share Register of the
Corporation will remain closed and the registration
of transfer suspended from 26th August, 1986 to 28th
September, 1986 (both days inclusive).

Notes:

1. The list of the share-holders shall be available
for purchase at the Head Office of the Corpora-
tion at a price of Re. 1/- (Rupee one only) per
copy from 6th September, 1986.
2. The last date for the receipt of nominations for
the election of a director shall be the 12th
September, 1986.
3. The last date for the deposit of proxies shall be
the 20th September, 1986.
4. The last date for the deposit of certified copies
of the resolutions appointing duly authorised
representatives by the Companies shall be
the 23rd September, 1986.
5. The last date for receipt of State Government's
order appointing any of its Officers as its
representative shall be the 29th September,
1986 before the time fixed for the meeting.

Sd/-
Secretary.

I, Charan Dass s/o Late Shri Kirpa Ram, Village
Dharam Kot, District Kangra have changed my name
to Om Parkash Pathania. All concerned to note please.

मैं, चरण दास सुपुत्र स्वर्गीय श्री किरपा राम, गांव धर्मकोट, जिला
कांगड़ा ने अपना नाम बदल कर ओम प्रकाश पठानिया रख लिया
है, सभी सम्बन्धितगण नोट करने की कृपा करें।

ओम प्रकाश पठानिया

सत्यापित।

सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।